वर्ष-10, अंक-12, सितम्बर-2025

मूल्य: ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

GST 2.0

महंगाई से राहत बजट में बचत

स्कूल पेयरिंग
शिक्षा की नई दिशा

क्या है स्कूल पेयरिंग ?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विद्यालयों को आपस में जोड़ा जा रहा है, ताकि संसाधनों का साझा उपयोग हो सके, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार और बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सके।

पेयरिंग के प्रमुख लाभ

- प्री-प्राइमरी से उच्च प्राथमिक तक निर्बाध शिक्षा
- विद्यालय के संसाधनों का बेहतर उपयोग
- छात्र-अध्यापक अनुपात बेहतर होगा
- ग्रेड लर्निंग एवं पियर लर्निंग से छात्र नामांकन में वृद्धि
- सामूहिक खेल, भाषण, नाटक, क्विज आदि प्रतिस्पर्धाएं
- डिजिटल और 21वीं सदी अनुकूल कौशलों का विकास
- प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, खेल मैदान, कम्प्यूटर लैब जैसी सुविधाएं

गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और आनंददायक शिक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियाँ

- **ऑपरेशन कायाकल्प**
  विद्यालयों में 19 मानकों पर संतृप्तीकरण
- **डी. बी. टी.**
  यूनीफार्म, बैग, स्टेशनरी के लिए ₹1200/छात्र
- **निपुण विद्यालय**
  48,061 विद्यालय निपुण घोषित
- **ASER/NAS की रिपोर्ट**
  गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि, उत्तर प्रदेश टॉप-10 में सम्मिलित
- **ट्रेनिंग**
  शिक्षकों की क्षमता में निरंतर संवर्द्धन

अन्य राज्यों में विद्यालयों की संविलियन संबंधी पहल

राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और असम

यहां क्या पड़ा प्रभाव?

बच्चों के नामांकन में वृद्धि • शिक्षकों की बेहतर तैनाती
बच्चों की उपस्थिति में सुधार

भ्रम न पालें

- पेयरिंग से किसी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा
- स्कूल का प्री-प्राइमरी/बालवाटिका के रूप में उपयोग
- शिक्षकों के पद में कहीं भी कोई कमी नहीं की जाएगी

भविष्य की तैयारी

मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय
(प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक)
₹1.42 करोड़ से स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, डायनिंग हॉल, सीसीटीवी, ओपन जिम

मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय
(प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक)
₹30 करोड़ से 1,500 छात्र-क्षमता, 30 स्मार्ट कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशाला, डिजिटल लाइब्रेरी, कौशल विकास केंद्र, खेल मैदान

UPGovt1Official | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP

काम दमदार डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

वर्ष- 10 अंक- 12

सितम्बर-2025

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक
स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार
विजय अरोड़ा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी
डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड
रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार
कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेल: winews.in@gmail.com
वेबसाइट: www.winews.in
सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

कवर स्टोरी
पेज-28

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूपी की अर्थव्यवस्था भी भरेगी नई उड़ान — पेज 03

भीड़ हादसों और त्रासदियों का सिलसिला कब थमेगा? — पेज 05

जातिवाद पर प्रतिबंध योगी सरकार का ऐतिहासिक कदम — पेज 12

भारत के प्रधानमंत्री को पूरा विश्व दे रहा सम्मान और विपक्ष कर रहा अपमान — पेज 14

फिल्म: मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा — पेज 52

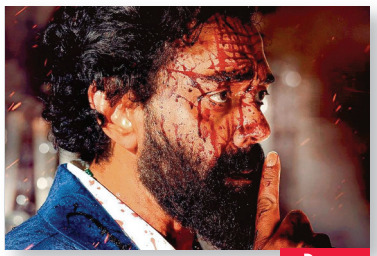

क्रिकेट: ये खिलाड़ी भी लेंगे सन्यास! — पेज 55

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 /9813221734 पर सम्पर्क करें।

जीएसटी की दरों में कटौती से लोगों को मिलेगी राहत

ललित कुमार
सम्पादक

सरकार की ओर से हाल में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती के एलान से माना जा रहा था कि इससे आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। उनके पास पैसों की बचत होगी, जिसे वे अन्य जरूरी वस्तुएं जुटाने पर खर्च कर सकेंगे। मगर इससे पहले कि जीएसटी की नई दरें लागू होतीं, लोगों की जेब पर एक और शुल्क का बोझ पड़ गया है। आनलाइन माध्यम से भोजन की आपूर्ति करने वाली कुछ कंपनियों ने अपने मंच शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। यानी आनलाइन भोजन मंगवाना अब महंगा हो जाएगा। इसका असर देशभर के लाखों लोगों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि 22 सितंबर से आपूर्ति शुल्क पर अठारह फीसद जीएसटी लागू होने पर आनलाइन भोजन मंगाने पर खर्च और बढ़ सकता है। ऐसे में यह सवाल भी अहम हो गया है कि सरकार ने जीएसटी सुधारों के तहत जो कदम उठाया है, क्या वास्तव में उसका लाभ उभोक्ताओं को मिल पाएगा या नहीं?

खबरों के मुताबिक, आनलाइन बुकिंग के माध्यम से भोजन परोसने वाली एक मुख्य कंपनी ने चुनिंदा बाजारों में अपना मंच शुल्क जीएसटी सहित पंद्रह रुपए कर दिया है। इसकी एक अन्य प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने भी अपना मंच शुल्क बढ़ाकर 12.50 रुपए (जीएसटी को छोड़कर) कर दिया है, जबकि एक अन्य कंपनी ने व्यापक उद्योग रुझानों के अनुरूप अपना मंच शुल्क संशोधित करके दस रुपए प्रति आर्डर कर दिया है। भोजन आपूर्ति कारोबार से जुड़े विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि 22 सितंबर से जब आपूर्ति शुल्क पर अठारह फीसद जीएसटी लागू हो जाएगा तो उपयोगकताओं पर प्रति आर्डर लगभग दो रुपए से लेकर ढाई रुपए से ज्यादा तक अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

जानकारों का कहना है कि जीएसटी में बदलाव से भोजन तैयार करने की लागत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उपभोक्ताओं पर शुल्क का अतिरिक्त बोझ डालने का औचित्य समझ से परे है। ऐसे में इन कंपनियों द्वारा मंच शुल्क में एक साथ की गई बढ़ोतरी खाद्य वितरण क्षेत्र में महंगाई के बढ़ते रुझान को रेखांकित करती है, जिससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या लाखों ग्राहकों के लिए सामर्थ्य और सुविधा अब भी साथ-साथ चल सकती हैं?

सरकार का तर्क है कि जीएसटी दरों में कटौती और इनके सरलीकरण से न केवल आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि घरेलू मांग भी बढ़ेगी, छोटे और बड़े उद्यमों को ज्यादा अवसर मिलेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा लोगों की आय बढ़ेगी, जिससे उनके खर्च की क्षमता भी बढ़ेगी। सरकार के इस फैसले को अमेरिकी शुल्क की चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल, सरकार का जोर घरेलू मांग और खपत बढ़ाने पर है।

कर में राहत से लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी और इसके परिणामस्वरूप खपत में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे अमेरिकी शुल्क का प्रभाव कम होगा। मगर यह तभी संभव होगा, जब जीएसटी दरों में कटौती का लाभ वास्तव में उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। अगर एक तरफ कर कम किया जाता है और दूसरी तरफ बढ़ा दिया जाता है तो जाहिर है कि मांग और खपत बढ़ने की उम्मीदों पर भी धुंधलका छाया रहेगा। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जीएसटी सुधारों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और जिन उत्पादों पर कर बढ़ा है, उसका बोझ सीधा उपभोक्ता पर न डाला जाए।

जानकारों का कहना है कि जीएसटी में बदलाव से भोजन तैयार करने की लागत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उपभोक्ताओं पर शुल्क का अतिरिक्त बोझ डालने का औचित्य समझ से परे है। ऐसे में इन कंपनियों द्वारा मंच शुल्क में एक साथ की गई बढ़ोतरी खाद्य वितरण क्षेत्र में महंगाई के बढ़ते रुझान को रेखांकित करती है, जिससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या लाखों ग्राहकों के लिए सामर्थ्य और सुविधा अब भी साथ-साथ चल सकती हैं?

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूपी की अर्थव्यवस्था भी भरेगी नई उड़ान

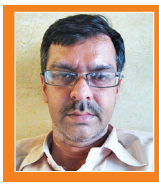

संजीव कुमार

देखा जाये तो आज से कुछ दशक पहले तक उत्तर प्रदेश निवेश और औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़ा हुआ माना जाता था। लेकिन 2017 में सत्ता में आने के बाद से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और केंद्र की सक्रिय नीतियों ने इस तस्वीर को बदल डाला है।

भारतीय विकास यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से परिवर्तन का वाहक रहा है। सड़कें, रेल और बिजली ने जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, उसी प्रकार आधुनिक भारत में हवाई अड्डे केवल यात्रियों के लिए सुविधाएँ नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले इंजन बन चुके हैं। 30 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) का उद्घाटन करेंगे, तो यह घटना केवल एक परियोजना का लोकार्पण नहीं होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की नई पहचान की शुरूआत होगी।

देखा जाये तो आज से कुछ दशक पहले तक उत्तर प्रदेश निवेश और औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़ा हुआ माना जाता था। लेकिन 2017 में सत्ता में आने के बाद से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और केंद्र की सक्रिय नीतियों ने इस तस्वीर को बदल डाला है। डिफेंस कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने यूपी को निवेशकों की सूची में अग्रणी स्थान दिलाया है। अब नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन इस यात्रा को निर्णायक मुकाम देने जा रहा है। देखा जाये तो यह एयरपोर्ट केवल हवाई यातायात का विस्तार नहीं करेगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान देगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश अब निवेश, उद्योग और पर्यटन का नया गढ़ बनने की ओर है।

एयरपोर्ट का स्वरूप और भविष्य की क्षमता को देखें तो आपको बता दें कि नोएडा एयरपोर्ट को चार चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाला रनवे और टर्मिनल तैयार है। अंतिम चरण तक यह 7 करोड़ यात्रियों को संभालने वाला भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार होगा। यही नहीं, उद्घाटन के पहले वर्ष में ही लगभग 60 लाख यात्री यहाँ से यात्रा करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि इसे कार्गो हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों के लिए यह वैश्विक सप्लाई चेन से सीधा जुड़ाव उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, यात्रियों और एयरलाइनों को नया विकल्प मिल गया है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले से ही यात्री दबाव चरम पर है। ऐसे में नोएडा एयरपोर्ट यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा।

नोएडा एयरपोर्ट से पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे महानगरों से सीधी उड़ानें मिलेंगी। भविष्य में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन भी होगा। इंडिगो एयरलाइंस को लॉन्च कैरियर बनाया गया है और अकासा एयर ने इसे हब के रूप में इस्तेमाल करने की घोषणा की है। यह न केवल यात्रियों को सुविधा देगा, बल्कि एयरलाइनों के लिए भी एक बड़ा अवसर होगा।

नोएडा एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर होने वाले सीधे असर को देखें तो हवाई अड्डे का निर्माण और संचालन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्तरों पर लाखों रोजगार पैदा

करेगा। सुरक्षा, ग्राउंड हैंडलिंग, होटल, पर्यटन, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में नई संभावनाएँ खुलेंगी।

इसके अलावा, यूपी अब विश्वस्तरीय हवाई सुविधा से लैस होगा। विदेशी कंपनियों के लिए ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल एरिया निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनेंगे। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल कंपनियाँ यहाँ आकर अपने कारोबार को विस्तार देंगी। साथ ही, आगरा, मथुरा और वृंदावन जैसे धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल अब वैश्विक पर्यटकों के लिए सहज पहुँच में होंगे। यह धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक उद्योग को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के किसान अपनी उपज सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँचा सकेंगे। फल, सब्जियाँ और दुग्ध उत्पादों का निर्यात आसान होगा। इससे फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज उद्योग को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, एनसीआर में ई-कॉमर्स कंपनियाँ– अमेजन, फ्लिपकार्ट या अन्य वैश्विक खिलाड़ी नोएडा एयरपोर्ट के माध्यम से अपनी सप्लाई चेन को और मजबूत करेंगे। यूपी धीरे-धीरे उत्तर भारत का लॉजिस्टिक्स हब बन सकता है।

देखा जाये तो दिल्ली-एनसीआर अब एशिया के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में गिना जाता है। लेकिन इसकी हवाई सुविधा लंबे समय से केवल दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्भर थी। नोएडा एयरपोर्ट इस दबाव को विभाजित करेगा और लोगों को वैकल्पिक एवं सुविधाजनक विकल्प देगा। इससे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद की कॉर्पोरेट कंपनियाँ लाभान्वित होंगी। साथ ही बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जैसे ज़िलों को रोजगार और औद्योगिक अवसर मिलेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट के ट्रैफिक का बोझ कम होगा। यानी, यह एयरपोर्ट पूरे एनसीआर को विकास का दूसरा इंजन प्रदान करेगा।

हम आपको यह भी बता दें कि नोएडा एयरपोर्ट केवल आकार में बड़ा नहीं है, बल्कि इसकी डिजाइन और सुरक्षा मानक भी विश्वस्तरीय हैं। यहां 350 से अधिक हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। यूनिफाइड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से 24७7 निगरानी है। इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग, फुल-बॉडी स्कैनर और ऑटोमेटेड ट्रे रिट्रीवल सिस्टम है। साथ ही क्राइम प्रिवेंशन थ्रू एनवायरनमेंटल डिजाइन पर आधारित ढाँचा है। इससे यात्रियों को सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा अनुभव मिलेगा। निश्चित रूप से यह एयरपोर्ट भारत के एविएशन सेक्टर को नई दिशा देगा और उत्तर प्रदेश को निवेश का वैश्विक गंतव्य बना देगा।

कुल मिलाकर देखें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन केवल एक भौतिक ढाँचे का लोकार्पण नहीं है। यह भारत की विकास गाथा का नया अध्याय है। उत्तर प्रदेश, जो कभी औद्योगिक रूप से पिछड़ा माना जाता था, अब नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। मोदी-योगी नेतृत्व ने मिलकर एनसीआर को दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट देकर जनता को आर्थिक सशक्तिकरण का उपहार दिया है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश की भरमार होगी, लाखों रोजगार पैदा होंगे और पर्यटन, कृषि तथा उद्योग सबको गति मिलेगी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नोएडा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए 21वीं सदी का परिवर्तनकारी प्रतीक है। यह हवाई अड्डा न केवल यात्रियों को सुविधा देगा बल्कि प्रदेश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी स्थान भी दिलाएगा।

जहां तक नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन की बात है तो आपको बता दें कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने कहा है कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होगा और उसके 45 दिन बाद उड़ान संचालन शुरू होने की उम्मीद है।

भीड़ हादसों और त्रासदियों का सिलसिला कब थमेगा ?

निश्चित ही भीड़ कोई संगठित चेतन शक्ति नहीं होती, यह एक उन्मादी प्रवाह है जिसमें व्यक्ति की सोच, विवेक और संवेदना विलीन हो जाती है। भीड़ के सामने व्यक्ति का आत्मनियंत्रण टूट जाता है और वह हिंसक, अनुशासनहीन और खतरनाक रूप ले लेती है।

उज्जवल रस्तौगी

तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) प्रमुख और सुपर अभिनेता से नेता बने विजय की चुनावी रैली के दौरान मची भगदड़ दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ स्तब्ध करने एवं पीड़ा देने वाली भी है। विजय की रैली में एक बार फिर भीड़ की बेकाबू उन्मत्तता ने 40 मासूम जिंदगियों को निगल लिया। सवाल उठता है कि आखिर कब तक ऐसी त्रासदियां हमारे समाज और शासन की नाकामी को उजागर करती रहेंगी? क्यों हमारी व्यवस्थाएं भीड़ को नियंत्रित करने में बार-बार विफल होती हैं और क्यों राजनीतिक दल, धार्मिक आयोजक, सिनेमा स्टार या अन्य तथाकथित 'सेलिब्रिटी' भीड़ के जमावड़े को सफलता का पैमाना मानकर उसे उकसाते हैं? भगदड़ में लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई, यह राज्य एवं टीवीके प्रायोजित एवं प्रोत्साहित हत्या है। पुलिस का बंदोबस्त कहां था? चीख, पुकार और दर्द और अभिनेता से नेता बने विजय को देखने की दीवानगी एक ऐसा दर्दनाक एवं खौफनाक वाकया है जो सुदीर्घ काल तक पीड़ित और परेशान करेगा। प्रशासन की लापरवाही, अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्थित प्रबंधन ने इस त्रासदी को जन्म दिया। यह घटना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों में दुनिया भर में सामने आई ऐसी घटनाओं की कड़ी का नया खौफनाक एवं दर्दनाक मामला है, जहाँ भीड़ नियंत्रण में चूक एवं प्रशासन, सत्ता एवं राजनीतिक दलों का जनता के प्रति उदासीनता का गंभीर परिणाम एवं त्रासदी का ज्वलंत उदाहरण है। अभिनेता विजय की चमक में प्रशंसकों की चीखें एवं आहें का होना और उसे नजरअंदाज करना, अमानवीयता की चरम पराकाष्ठा है। दुर्घटना होने एवं आम लोगों की मौतें दुखद एवं शर्मनाक है। इस राज्य में दशकों से विशाल राजनीतिक सभाओं की संस्कृति रही है, जिसे फिल्म और राजनीति के मेल ने पोषित किया है। सीएन अन्नादुरई, एमजी रामचंद्रन और जयललिता, सभी मुख्यमंत्री बनने से पहले फिल्मी सितारे थे। उनकी रैलियों में अक्सर लाखों लोग आते थे। स्टार पावर और राजनीति का मेल अधिकारियों के लिए भीड़ को नियंत्रित रखना मुश्किल बना देता है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके अभी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन इसकी रैलियों में प्रशंसकों की अहमियत को कमतर आंकने के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम ने न केवल राजनेताओं को बल्कि सिने स्टार को भी दागी किया है। घटना ने एक बार फिर हमारे अवैज्ञानिक व लाठी भांजने वाले भीड़ प्रबंधन की ही पोल खोली है।

करीब तीन महीने पहले जून में बंगलूरू में आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में भी करीब एक दर्जन लोग मारे गए थे। हालांकि, शनिवार रात करूर में उमड़ी भीड़ किसी राजनीति जमावड़े से अधिक अपने सुपरस्टार को करीब से देखने के लिए बेताब प्रशंसकों की थी। इसी उन्माद में, जब एक पेड़ की डाली पर चढ़े कुछ समर्थक अभिनेता की प्रचार गाड़ी के पीछे खड़े लोगों पर गिर पड़े, तो दहशत फैल गई और रैली एक हादसे में बदल गई। इसी में करीब 40 लोगों के मरने और कइयों के घायल होने की खबरें हैं। तमिलनाडु में, 2026 में चुनाव होने हैं और टीवीके बेशक मैदान में उतरने की घोषणा कर चुकी हो, लेकिन दुर्घटना के बाद विजय जिस तरह से जल्दबाजी में चार्टर्ड फ्लाइट से चेन्नई चले गए, उससे यही साबित होता है कि अभी उन्हें राजनीति

करना, अमानवीयता की चरम पराकाष्ठा है। दुर्घटना होने एवं आम लोगों की मौतें दुखद एवं शर्मनाक है। इस राज्य में दशकों से विशाल राजनीतिक सभाओं की संस्कृति रही है, जिसे फिल्म और राजनीति के मेल ने पोषित किया है। सीएन अन्नादुरई, एमजी रामचंद्रन और जयललिता, सभी मुख्यमंत्री बनने से पहले फिल्मी सितारे थे। उनकी रैलियों में अक्सर लाखों लोग आते थे। स्टार पावर और राजनीति का मेल अधिकारियों के लिए भीड़ को नियंत्रित रखना मुश्किल बना देता है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके अभी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन इसकी रैलियों में प्रशंसकों की अहमियत को कमतर आंकने के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम ने न केवल राजनेताओं को बल्कि सिने स्टार को भी दागी किया है। घटना ने एक बार फिर हमारे अवैज्ञानिक व लाठी भांजने वाले भीड़ प्रबंधन की ही पोल खोली है।

करीब तीन महीने पहले जून में बंगलूरू में आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में भी करीब एक दर्जन लोग मारे गए थे। हालांकि, शनिवार रात करूर में उमड़ी भीड़ किसी राजनीति जमावड़े से अधिक अपने सुपरस्टार को करीब से देखने के लिए बेताब प्रशंसकों की थी। इसी उन्माद में, जब एक पेड़ की डाली पर चढ़े कुछ समर्थक अभिनेता की प्रचार गाड़ी के पीछे खड़े लोगों पर गिर पड़े, तो दहशत फैल गई और रैली एक हादसे में बदल गई।

इसी में करीब 40 लोगों के मरने और कइयों के घायल होने की खबरें हैं। तमिलनाडु में, 2026 में चुनाव होने हैं और टीवीके बेशक मैदान में उतरने की घोषणा कर चुकी हो, लेकिन दुर्घटना के बाद विजय जिस तरह से जल्दबाजी में चार्टर्ड फ्लाइट से चेन्नई चले गए, उससे यही साबित होता है कि अभी उन्हें राजनीति के कई सबक एवं राजनीतिक मूल्यों को सीखने हैं। क्योंकि आखिर वह अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? टीवीके ने तीस हजार लोगों की अनुमति ली थी और इसी हिसाब से पुलिस की तैनाती भी हुई थी। लेकिन शाम होते-होते इसके दोगुने लोग अभिनेता की एक झलक पाने को मौजूद थे। निश्चित ही भीड़ कोई संगठित चेतन शक्ति नहीं होती, यह एक उन्मादी प्रवाह है जिसमें व्यक्ति की सोच, विवेक और संवेदना विलीन हो जाती है। भीड़ के सामने व्यक्ति का आत्मनियंत्रण टूट जाता है और वह हिंसक, अनुशासनहीन और खतरनाक रूप ले लेती है।

यही कारण है कि क्रिकेट मैच से लेकर राजनीतिक रैली, धार्मिक आयोजन और फिल्मी सितारों की झलक तक, हर जगह भीड़ का जुनून कई बार मौत का तांडव बन जाता है। इतिहास गवाह है कि भीड़ की हिंसा ने न केवल जानें ली हैं, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी चोट पहुंचाई है। 1984 के सिख विरोधी दंगे, 1992 का बाबरी मस्जिद प्रकरण, गुजरात हिंसा, धार्मिक जुलूसों में भगदड़ या तीर्थयात्राओं में दबकर मरने वाले सैकड़ों लोग- इन सबकी जड़ में 'भीड़' है। भीड़ के भीतर छिपा हुआ सामूहिक उन्माद किसी भी क्षण हिंसा, लूट और तबाही में बदल जाता है।

भारत में भीड़ से जुड़े हादसे अनेक आम लोगों के जीवन का ग्रास बनते रहे हैं। धार्मिक आयोजनों हो या खेल प्रतियोगिता, राजनीतिक रैली हो या सांस्कृतिक उत्सव लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, जहाँ भीड़ प्रबंधन की मामूली चूक भयावह त्रासदी में बदलते हुए देखी जाती रही है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 में दक्षिण कोरिया के इटावन हैलोवीन समारोह में अत्यधिक भीड़ के कारण 150 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह, वर्ष 2015 में मक्का में हज के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के रत्नागढ़ मंदिर में ढाँचागत कमियों से प्रेरित भगदड़ के कारण 115 लोगों की मौत हो गई थी।

हालही में महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन एवं प्रयागराज में हुए हादसे एवं हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में बिजली का तार टूटने और करंट फैलने की एक अफवाह ने कई जानें ले लीं, जिसने धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। आग, भूकंप, या आतंकी हमलों जैसी आपातकालीन स्थितियाँ में भी भीड़ प्रबंधन की पोल खुलती रही है। आखिर दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में हम भीड़ प्रबंधन को लेकर इतने उदासीन क्यों है? बड़े आयोजनों-भीड़ के आयोजनों में भीड़ बाधाओं को दूर करने के लिए, भीड़ प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, सुरक्षाकर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना, जन जागरूकता बढ़ाना और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना अब नितान्त आवश्यक है।

विजय और उनके समर्थक कुछ भी कहें, वे अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। इसलिए और नहीं बच सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी रैली में आने वाले लोगों की संख्या के बारे में भी कोई सही जानकारी नहीं दी थी। बहुत संभव है कि इसके चलते पुलिस ने भी पर्याप्त व्यवस्था न की हो। तमिलनाडु में सेलेब्रिटी स्टेटस वाले लोगों के प्रति दीवानगी कुछ ज्यादा ही है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हर त्रासदी के बाद सरकारें और पुलिस प्रशासन सिर्फ 'जांच समिति' और 'मुआवजा' देने की घोषणा करके अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं। न तो कोई ठोस नीतियां बनती हैं, न ही आयोजकों पर कठोर जिम्मेदारी तय की जाती है।

आयोजकों की लापरवाही और प्रशासन की ढिलाई इन घटनाओं की सबसे बड़ी वजह हैं। यदि समय रहते सुरक्षा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की सख्त व्यवस्था हो, तो ऐसी भयावह स्थितियों को टाला जा सकता है। भीड़ की त्रासदी केवल प्रशासनिक विफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक मनोविज्ञान का भी प्रतिबिंब है। आमजन की 'हीरो-दीवानगी' और अंधभक्ति किसी भी भीड़ को अनियंत्रित बना देती है। जब तक नागरिक चेतना में संयम और विवेक नहीं आएगा, तब तक भीड़ केवल संख्या का खेल बनी रहेगी और उसका परिणाम विनाशकारी होता रहेगा।

एडिशनल कमिश्नर (आईपीएस) केशव चौधरी इस नाम को सुनकर भागे थे चित्रकूट के डकैत

इंद्रेश शर्मा

गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर केशव चौधरी 2009 बेच के आईपीएस है । मूलरूप से बिहार के दरभंगा के रहने वाले केशव कुमार चौधरी 44 साल के हैं। उनका जन्म 9 जनवरी 1981 को बिहार के दरभंगा जिले में दयानाथ चौधरी के परिवार में हुआ था । उन्होंने इतिहास, राजनीतिशास्त्र और हिंदी से स्नातक तक की पढ़ाई की है अभी तक वे आगरा पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर और झांसी में डीआईजी पर तैनात रहे। इससे पहले वे बहराइच में एसएसपी के पद पर तैनात रहे थे। केशव कुमार चौधरी को 2013 में सीनियर ग्रेड में प्रोन्नत किया गया। वे एक जनवरी 2023 को डीआईजी ग्रेड में प्रोन्नत किए गए। उनके बेहतर कार्यों के लिए डीजीपी का सिल्वर डिस्क 2021 और गोल्ड डिस्क 2024 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मिला था। प्रदेश में उनकी गिनती तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस में होती हैं। झांसी और आगरा में रह चुके है तैनात, चित्रकूट के डकैतों का कर चुके है सफाया। तभी मुख्यमंत्री योगी जी ने इन पर भरोसा जताते हुए गाजियाबाद जिले में तैनाती दी है।

इनके बारे में कहा जाता है कि पीड़ितों की फरियाद गंभीरता से सुन उस पर विधि अनुसार निर्णय लेना उनका अंदाज है इसका जीता जागता उदाहरण जब देखने को मिला जब वह प्रतिदिन की तरह जनता से सीधे तौर पर जनता की परेशानियों को सुन रहे थे तभी एक महिला ने अपनी फरियाद यह कह सुनाई कि उसके परिवार वाले उसकी शादी के खिलाफ और उसे मारने की धमकी दे रहे है तभी महिला की आप बीती सुन उन्होंने निर्णायक अंदाज में महिला को आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं अगर ऐसा दुबारा होता है तो वह निसंकोच उन्हें इस बाबत दुबारा बता सकती है और उनकी कानून के तहत पूरी मदद की जाएंगी।

त्वरित, कठोर और समयानुकूल निर्णय क्षमता ही है नरेन्द्र मोदी की पहचान

आज मोदी के भारत को दुनिया का कोई देश या दुनिया का कोई नेता हल्के में नहीं ले सकता। इसका कारण भी है भारत आज आंख में आंख डाल कर बात करने की हैसियत रखता है। ट्रंप की बौखलाहट से इसे आसानी से समझा जा सकता है।

राहुल अग्रवाल

मार्निंग कंसल्ट की वैश्विक मंच पर लोकप्रियता के ताजातरीन सर्वे में एक बार फिर 75 वर्षीय नरेन्द्र दामोदर दास मोदी की लोकप्रियता या यों कहें कि एप्रूवल रेट 75 प्रतिशत रही है। यह विश्व के अन्य नेताओं की तुलना में कहीं अधिक है तो दूसरी और पिछले दिनों प्यू रिसर्च की रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा जताने वाले केवल 40 प्रतिशत लोग ही रह गए और इनमें भी केवल मात्र 15 फीसदी ही ऐसे लोग है जो पूरी तरह से ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं। चुनाव के समय 81 प्रतिषत भरोसे लायक नेता पर 40 प्रतिशत अमेरिकीयों का भरोसा और इनमें से भी 25 प्रतिशत का थोड़ा भरोसा तो केवल 15 प्रतिशत अमेरिकी ही ट्रंप पर पूरी तरह से भरोसा जता रहे हैं। 59 प्रतिशत अमेरिकीयों को तो ट्रंप पर अब बिलकुल भी भरोसा नहीं रहा है। एक बात और साफ हो जानी चाहिए कि मार्निंग कंसल्ट के इस सर्वे में दूसरे पायदान पर रहने वाले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति लीजे म्युंग को 59 प्रतिशत और अर्जेंटिना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को 57 प्रतिशत का एप्रूवल मिला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एप्रूवल देश में ही नहीं विदेशों में भी एक दंबग नेता और साफ सुथरी छवि के कारण है। इसके साथ ही कूटनीति, तकनीक, रक्षा, अर्थव्यवस्था और किसी के सामने नई झुकने की जीद ने और अधिक लोकप्रियता बढ़ा दी है। सबसे खासबात यह है कि विरोधी चाहे कितना भी शोर मचाये इसमें कोई दो राय नहीं और इससे भी बढ़कर कि आपरेशन सिन्दुर को लेकर देशवासियों और विदेशियों किसी को भी नरेन्द्र मोदी और सेना के कथन पर किसी

तरह का कोई संदेह नहीं है। देर सबेर और गाहे बेगाहे पाकिस्तान तक ऑपरेशन सिन्दुर की टीस को व्यक्त कर ही देता है। ऐसे में विरोधियों द्वारा ऑपरेशन सिन्दुर पर जिस तरह से नकारात्मकता व्यक्त की जाती हैं वह कहीं ना कहीं मोदी और मोदी सरकार की विश्वसनीयता को और अधिक बढ़ाने में ही सहायक है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि नरेन्द्र मोदी अपनी जीवन की अमृतवेला मना रहे है। 75 साल के नरेन्द्र मोदी जिस अदम्य साहस और दृढ़ता का परिचय दे रहे हैं और खासतौर से जिस तरह से अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने से पूरी तरह नकार कर लगता है अब तो ट्रंप को ही झुकने को मजबूर होने जैसे हालात कर दिए हैं। ट्रंप शायद भूल गए कि यह आज का और मोदी का हिन्दुस्तान है।

आज मोदी के भारत को दुनिया का कोई देश या दुनिया का कोई नेता हल्के में नहीं ले सकता। इसका कारण भी है भारत आज आंख में आंख डाल कर बात करने की हैसियत रखता है। ट्रंप की बौखलाहट से इसे आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल आज के दौर में वैश्विक नेता के रुप में बोल्ड होने, एग्रेसिव होने, कठोर व त्वरित निर्णय लेने वाले नेता लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। अच्छे बुरे परिणाम की चिंता कर निर्णय की उहापोह में फंसे नेता आज के लोगों की पसंद हो ही नहीं सकते। इसका बड़ा कारण दुनिया में वैश्विक संकटों का दौर चलना है। पर यह भी समझ लेना होगा कि दुनिया के लोग ट्रंप जैसे अंहकारी, तुगलकी निर्णय करने वाले, गली मौहल्ले के दादाओं जैसे व्यवहार करने वाले और अपने नासमझी भरे निर्णयों और फिर उन निर्णयों पर मुहं की खाने वाले नेताओ को भी पसंद नहीं करते। संकटों के दौर में लोगों का यह मानना रहता है कि हमें आलोचना प्रत्यालोचना या आगा पीछा सोच कर निर्णय लेने वाला नहीं अपितु त्वरित और कठोर निर्णय लेने वाला नेता चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेन्द्र मोदी इस पर खरे उतरे हैं।

जहां तक देश और देश में मोदी विरोधियों की बात है तो यह भी अब तक साफ हो गया है कि मोदी के विरोध में जो जो नारे गढ़े गए या अभियानों में जो मोदी विरोध की आवाज बने वह सब विरोधियों पर ही भारी पड़े है। इसकी शुरूआत 2007 में गोदरा कांड के बाद चुनाव के बाद का नारा मौत का सौदागर हो या आज चौकीदार चोर है सभी नारे उल्टे पड़े हैं और देशवासियों ने इन्हें सिरे से नकारा है। चौकीदार चोर है का उत्तर देते हुए स्वयं मोदी ने इसका उपयोग मैं भी चौकीदार का जबावी नारा देकर उत्तर दिया।

नारों की यह एक लंबी फेहरिस्त है जिससे देशवासी अवगत है। अब आज वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाकर या संविधान बचाओं का नारा देकर मोदी विरोध में हवा बनाने व बिहार आदि के चुनाव जीतने का सपना पाल रहे हैं पर कहीं पहले की तरह सेल्फ गोल ही साबित ना हो जाये इससे नकारा नहीं जा सकता। राममंदिर, कश्मीर में धारा 370 हटाने, कश्मीर युवाओं को मुख्यधारा में लाने, ऑपरेशन सिन्दुर, एयर स्ट्राइक, जनधन खाते, डिजिटल भुगतान, जन औषधी केन्द्र, आयुष्मान योजना, गिग इकोनोमी, रक्षा आयुधों का देश में ही उत्पादन व निर्यात, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप, यूनिकोर्न, विदेशी निवेश, सडक परिवहन विकास, आदि आदि सभी क्षेत्रों में विकास का जो दौर दिखाई दे रहा है यह ठोस और त्वरित योजनावद्ध निर्णयों का ही परिणाम है। यह तो केवल बानगी मात्र है। आज आतंकवादी गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई, नक्सलवादी गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं, सांप्रदायिकता पर रोक लगी है, पत्थरबाजी नहीं दिखती, सपाट यातायात दिखाई दे रहा है यह और इसके अलावा भी बहुत कुछ सामने हैं।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि विश्वसनीयता एक दिन में या एक काम से नहीं बनती। इसके साथ ही केवल व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने से भी कोई खास हासिल नहीं हो सकता। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की आदत डाले तो शायद आमजनता में अधिक प्रभावी तरीके से अपनी बात रख कर लोगों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। जब राष्ट्रीय अस्मिता पर और सेना के पराक्रम को प्रश्नों में उभारा जाता है तो लाख कमियों के बावजूद सच्चा राष्ट्रप्रेमी नागरिक इसे स्वीकार नहीं पाता। यही कारण है कि मोदी जी को जितना निशाना बनाया जाता है मोदी उस निशाने से और अधिक निखार के साथ उभरते आ रहे हैं। आज जब ट्रंप भारत की अर्थ व्यवस्था को नकारते हैं तो यह देशवासियों के गले उतरने वाली बात नहीं होती। इसी तरह से जब ऑपरेशन सिन्दुर पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है तो आमजन इसे देश के खिलाफ आवाज और सेना के असम्मान के रुप में देखता है। जब संविधान की प्रति उठाकर संविधान बचाओ की बात करते हैं तो उनकी सरकार के समय ही संसद से पास अधिसूचना को सार्वजनिक रुप से फाड़ने को याद करते हैं। जीएसटी को लेकर प्रश्न उठाते हैं तो आज इससे मिल रही राहत को जनता कैसे नकार सकती है। इसलिए सकारात्मक विरोध के साथ आगे आकर ही मोदी और मोदी की नीतियों का पार पा सकते हैं।

संसद और विधानसभाओं में गतिरोध का दौर चलता है, खुली चचाएं हो नहीं पाती, सत्र सालों साल छोटे होते जा रहे हैं। आधी आधी रात तक होने वाली चचाएं अब बीते दिनों की बात हो गई है तो ऐसे में केवल आरोप प्रत्यारोप के भरोसे मोदी पर जीत की बात करना बेमानी होगा। दूसरी बात यह कि हम बड़ी लकीर खींच कर ही दूसरी लकीर को छोटी बता सकते हैं हो इसका उल्टा रहा है और प्रयास लकीर से ही छेड़ छोड़ कर छोटी दिखाने के प्रयास किये जाते हैं तो यह गले नहीं उतरती। यह सब समझने वाली बात हो गई है। मोदी जी की अमृत वेला में शतायु होने की कामना के साथ आज देश उनकी और देख रहा है। ऐसे में मोदी जी के नेतृत्व और निवृति की बात करना पूरी तरह से बेमानी होगी। देश को अभी मोदी जी और उनके जैसे नेतृत्व की आवश्यकता है जिससे आजादी के शताब्दी वर्ष तक देश विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन कर उभर सके।

उम्मीदों की चिप से हौसलों की उड़ान भरता भारत

भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिये उत्सुक है। तभी सेमीकॉन इंडिया-2025 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में बड़े बदलाव की नींव रखेगी।

चरण सिंह

भारत ने तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया इतिहास रचते हुए अपना पहला पूर्णतया स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर तैयार कर एक तकनीकी क्रांति को आकार दिया है। यह उपलब्धि न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है। भारत ने इस तकनीकी क्रांति की तरफ कदम बढ़ते हुए आत्मनिर्भर एवं स्वदेशी तकनीकी प्रगति को नये आयाम दिये हैं। पहला पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित करने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिये इसरो की सेमीकंडक्टर लैब साक्षी बनी है। पहली मेड इन इंडिया चिप का उत्पादन गुजरात के साणंद स्थित पायलट प्लांट से शुरू होगा। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत 18 अरब डॉलर से ज्यादा के कुल निवेश वाली दस सेमीकंडक्टर परियोजनाएं देश में चल रही हैं, अब भारत को इस तरह की तकनीक के लिये विदेशों के पराधीन नहीं होना होगा। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले चिप क्षेत्र में भारत की यह दस्तक उत्साह जगाने वाली है, निश्चित ही इससे भारत की ताकत बढेगी और तकनीक के साथ-साथ यह आर्थिक विकास को तीव्र गति देगा। फिलहाल आधुनिक समय की इस जादुई चिप के उत्पादन में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों का वर्चस्व है। विशेषतः भारत की यह जादूई उपलब्धि अमेरिका को आइना दिखाने वाली है, ट्रंप को यह एक बड़ा झटका है।

भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिये उत्सुक है। तभी सेमीकॉन इंडिया-2025 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में बड़े बदलाव की नींव रखेगी। हालांकि, इस राह में अभी कई चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद है कि छह सौ अरब डॉलर वाले वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर की हो सकती है, जिससे भारत अनेक मोर्चे पर सफलता के परचम फहरायेगा। इस स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अर्धचालक प्रयोगशाला ने अभिकल्पित किया है और इसे 'विक्रम' नाम दिया गया है। यह अंतरिक्ष-मानक माइक्रोप्रोसेसर है, जो मुख्यतः अंतरिक्ष अभियानों और रॉकेट प्रणालियों में प्रयोग के लिए तैयार किया गया है। इसरो ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) चंडीगढ़ के साथ मिलकर दो स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं। यह माइक्रोप्रोसेसर प्रक्षेपण यानों के नेविगेशन और नियंत्रण में मदद करेंगे। विक्रम 3201 पूरी तरह भारत में बना पहला 32-बिट प्रोसेसर है। इस कदम से इसरो को विदेशी प्रोसेसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जिससे अंतरिक्ष में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। निश्चित ही इससे भारत ने महाशक्ति बनने की ओर अपनी गति को तीव्रता दी है, जिससे अमेरिका हिला और दुनिया

भारत की ताकत से रू-ब-रू हो रही है।

अब तक भारत को अनेक जटिल अंतरिक्ष अभियानों के संचालन हेतु विदेशी सूक्ष्म-प्रक्रमकों और अर्धचालक पट्टिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। यह विदेशी निर्भरता न केवल आर्थिक दृष्टि से बोझिल थी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण थी। 'विक्रम' माइक्रोप्रोसेसर के निर्माण से भारत ने इस निर्भरता की बेड़ियों को तोड़ा है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशक्त कदम बढ़ाया है। निस्संदेह, भारत को चिप उत्पादन क्षेत्र में एक दिग्गज देश बनने के लिए निरंतर निवेश, अनुसंधान-विकास और विनिर्माण की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिये निरन्तर प्रयासरत है। हाल ही में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से उम्मीद जगी है कि वह वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करने में भारत के लिये मददगार साबित हो सकता है। यह सुखद ही है कि भारत में चिप उत्पादन परियोजनाओं में जापानी निवेश बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं भारत को ऐसे ही विकास के नये शिखरों पर आरोहण कराने का सशक्त माध्यम बन रही है।

निश्चित रूप से मोदी सरकार के प्रयासों से भारत चिप उत्पादन के वैश्विक महत्वाकांक्षी अभियान की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ सकता है। दरअसल, डिजिटल डिवाइसों का मस्तिष्क कहा जाने वाला सेमीकंडक्टर कंप्यूटर, मोबाइल, राउटर, कार, सैटलाइट जैसे उन्नत डिजिटल डिवाइस तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन उपकरणों की कार्यकुशलता उन्नत चिप की ताकत पर निर्भर करती है। साधारण शब्दों में कहें चिप पतली सिलिकॉन वेफर पर बने लाखों-करोड़ों ट्रांजिस्टरों का संजाल है। जो कंप्यूट करने, मेमोरी प्रबंधन व सिग्नल प्रोसेस करके डिवाइस को उन्नत बनाती है। उम्मीद है कि भारत का स्वेदशी चिप इस साल के आखिर तक बाजार में आ सकेगी। जिसका असर जियोपॉलिटिक्स पर तो होगा ही, नये रोजगार सृजन का वातावरण भी बनेगा, भारत तकनीकी विकास के नये आयाम उद्घाटित करते हुए विश्व को अचंभित भी करेगा। निश्चय ही भारत यदि अनुसंधान-विकास व व्यापार सुगमता की स्थितियां निर्मित कर लेता है तो हमारी सेमीकंडक्टर आयात के लिये दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे हम वैश्विक दबाव से मुक्त होकर अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बना सकते हैं।

32-बिट क्षमता का अर्थ है कि यह माइक्रोप्रोसेसर अधिक व्यापक स्मृति का उपयोग कर सकता है और जटिल संगणकीय कार्यों को तीव्र गति से संपन्न कर सकता है। अंतरिक्ष अभियानों में जहाँ प्रत्येक क्षण और प्रत्येक संकेत का महत्व होता है, वहाँ इस प्रकार की क्षमता अत्यंत आवश्यक है। यह केवल गति और कार्यकुशलता नहीं देता बल्कि विकिरण-सहनशीलता और दीर्घकालीन स्थिरता जैसे गुण भी समाहित करता है। अंतरिक्ष में प्रबल विकिरण, तापमान का उतार-चढ़ाव और कठोर परिस्थितियाँ होती हैं, जिनका सामना सामान्य माइक्रोप्रोसेसर नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार का अंतरिक्ष-योग्य माइक्रोप्रोसेसर ही मिशनों की सफलता का आधार बन सकता है।

इस उपलब्धि का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके लिए आवश्यक रूपांकन, निर्माण और परीक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया भारत में ही सम्पन्न की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत अब केवल प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता नहीं बल्कि उसका सर्जक भी है। सूक्ष्म-संगणक की यह अभिकल्पना केवल एक चिप का निर्माण नहीं है, यह भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा, उसकी दूरदृष्टि और आत्मविश्वास का परिचायक है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सफलता हासिल करने की दिशा में भारत का एक सशक्त पक्ष यह भी है कि दुनिया के लगभग बीस फीसदी चिप डिजाइन इंजीनियर भारत में हैं। दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी क्षेत्र में कामयाबी के लिये भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सरकार बड़ी घरेलू कंपनियों को संबल देने के लिये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी डीएलआई के तहत दिए जा रहे लाभ के विस्तार के साथ ही, इसके तहत दिये जाने वाले अनुदान को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जिसके तहत महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादन परियोजनाओं के लिये केंद्र व राज्यों से प्रोत्साहन के रूप में परियोजना की कुल लागत का सत्तर फीसदी मिलना जारी रह सकता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में गेम चेंजर टेक क्रांति माना जा रहा है।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थान पहले ही 'शक्ति' और 'वेगा' जैसे स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर पर काम कर चुके हैं। इन प्रयासों ने आधारभूमि तैयार की और आज 'विक्रम' के रूप में वह प्रयास मूर्त रूप में सामने आया है। यह न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र बल्कि रक्षा, चिकित्सा उपकरणों और संचार प्रणाली में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। निश्चित ही चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन, उपकरण-समूह की उपलब्धता, संगणक-कार्यक्रमों का विकास, अनुप्रयोग-तंत्र का विस्तार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणन जैसी प्रक्रियाएँ अभी पूरी करनी होंगी। किंतु भारत ने जिस आत्मविश्वास के साथ इस दिशा में पहला कदम रखा है, वह आश्वस्त करता है कि भविष्य में हम और भी उन्नत सूक्ष्म-प्रक्रमक तैयार करने में सक्षम होंगे। 'विक्रम' केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह भारत की स्वाभिमानी यात्रा का घोष है। यह घोषणा है कि अब भारत केवल विज्ञान का अनुयायी नहीं बल्कि विज्ञान का निमार्ता और मार्गदर्शक बनने की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना अब शब्दों में नहीं, ठोस उपलब्धियों में आकार ले रही है।

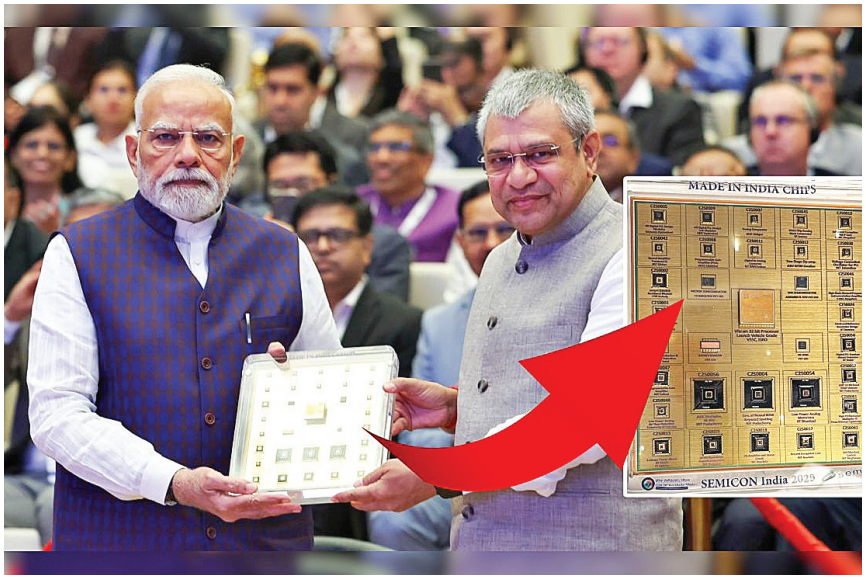

जातिवाद पर प्रतिबंध योगी सरकार का ऐतिहासिक कदम

योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक आदर्श समाज व्यवस्था निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध आवाज ही नहीं उठाई, अपने राजनीतिक जीवन के अनेक उदाहरणों से समाज को सक्रिय प्रशिक्षण भी दिया।

रवि जैन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है। उन्होंने समाज में जाति आधारित विद्वेष को ही नहीं बल्कि विभेद को भी समाप्त करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए सद्भाव के साथ सबके विकास को बल देने का सूझबूझभरा फैसला लिया है। इस फैसले के अन्तर्गत उन्होंने जाति-आधारित रैलियों, सार्वजनिक प्रदर्शनों और पुलिस रिकॉर्ड में जाति संबंधी उल्लेखों पर रोक लगा दी है। यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया, लेकिन इसका वास्तविक महत्व इससे कहीं अधिक है। यह केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं बल्कि समाज को जातिगत बंधनों से मुक्त करने की दिशा में क्रांतिकारी प्रयास है। राजनीतिक दलों ने जाति आधारित वोटों को लुभाने एवं राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेंकने के लिये समाज को बांटा है। यह गौर करने की बात है कि जाति आधारित संगठनों और रैलियों की बाढ़ आ गई है, जिससे एक-एक जाति के अनेक संगठन बने और इन जातिगत संगठनों ने सड़कों पर उतर कर न केवल सार्वजनिक व्यवस्था, इंसान-इंसान के बीच दूरियां-विद्वेष बढ़ा दिया बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी क्षत-विक्षत कर दिया।

भारतीय समाज में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं। जाति व्यवस्था ने कभी सामाजिक पहचान और श्रम विभाजन का आधार बनकर काम किया, लेकिन समय के साथ यह भेदभाव, असमानता और सामाजिक विद्वेष का कारण बन गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था- 'जातिवाद समाज की आत्मा को खोखला करता है।' डॉ. भीमराव आंबेडकर ने तो इसे भारतीय प्रगति की सबसे बड़ी बाधा बताया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी जातिवाद ने राजनीति और समाज दोनों में गहरी पैठ बनाई और देश की एकता को कमजोर करने का काम किया। जाति-आधारित राजनीति ने सत्ता के समीकरण तो बदले लेकिन समाज को बांटने का काम किया। चुनाव के समय उम्मीदवारों का चयन जातिगत समीकरणों के आधार पर होता रहा। समाज के बंटवारे का यह खेल लोकतंत्र के स्वस्थ आदर्शों के लिए चुनौती बना। जातिगत रैलियां और प्रदर्शन सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करते रहे। पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख अपराधी को अपराधी नहीं बल्कि किसी जाति का प्रतिनिधि बना देता था, जिससे कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ता था। इन जटिल स्थितियों में योगी सरकार का यह निर्णय विषमताओं एवं विसंगतियों को समाप्त करने की दिशा में एक नया अध्याय है। यदि इसे सख्ती और ईमानदारी से लागू किया गया तो निश्चित ही समाज में सौहार्द, भाईचारा और समानता का वातावरण

बनेगा। जाति-आधारित पहचान की जगह व्यक्ति की योग्यता, आचरण और योगदान को महत्व मिलेगा।

किसी जाति के प्रति लगाव दशार्ने के लिए किसी अन्य जाति को नीचा दिखाने की भी गलत परंपरा पड़ती दिख रही है। जाति आधारित पोस्टर या प्रतीक न केवल गलियों में, मकानों पर बल्कि अपने वाहनों पर भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में, परस्पर भेद, ऊंच-नीच की भावना बढ़ती जा रही है। ऐसे भेद को मिटाने की मांग उठती रही है। समाज के लिए चिंतित रहने वाले लोग यही चाहते हैं कि जातिगत झंडों और पोस्टरों पर एक हद तक लगाम लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा साहस राजनीतिक स्वार्थों के चलते अब तक किसी भी राजनेता ने नहीं दिखाया, लेकिन योगी सरकार ने यह साहस दिखाया है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। योगी सरकार द्वारा जारी 10 सूत्रीय दिशा-निर्देश में यह बात विशेष रूप से गौर करने लायक है कि अब जाति के नाम, नारे या स्टिकर वाले वाहनों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत चालान किया जाएगा। यहां तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी जाति को दशार्ने से बचा जाएगा। अभी तक होता यह है कि अपराधी जाति के आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं और मजबूत हो जाते हैं।

यह बहुत अफसोस की बात है कि विशेष रूप से चुनाव के समय जाति आधारित बैनरों की बाढ़ आ जाती है। राजनीतिक दल एवं नेता जातिगत समीकरणों से समाज को बांटने में जुट जाते हैं। लेकिन अब यूपी सरकार की मंशा सराहनीय है और इन दिशा-निदेर्शों को पूरी तरह से लागू करने की जरूरत है। वाकई समाज से अपराध को मिटाने के लिए अपराधी की जाति देखना गैर-वाजिब है। हां, यह सावधानीपूर्वक कुछ मामलों में जाति का उल्लेख करने की छूट दी गई है। जैसे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल होता रहेगा। वाकई, कुछ मामले ऐसे होते हैं, जहां जाति की चिंता या उल्लेख जरूरी हो जाता है। यह भूलना नहीं चाहिए कि जाति आधारित भेदभाव अभी भी कई जगहों पर देखने को मिल जाता है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर भेदभाव की शिकायतें अक्सर आती हैं, ऐसे में, प्रशासन को ज्यादा सजग रहना पड़ेगा। निर्देश जारी हो जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि जातिगत भेदभाव के बिंदुओं को खोज-खोजकर मिटाने की ईमानदार पहल भी जरूरी है। सामाजिक चिंतक विनोबा भावे कहा करते थे 'जाति का भेद मिटेगा तो समाज में भाईचारा और सहयोग की भावना पनपेगी।' वास्तव में जातिवाद केवल सामाजिक समस्या नहीं बल्कि मानसिकता का रोग है। जब तक समाज इसे स्वीकार करता रहेगा, तब तक सच्चा विकास संभव नहीं।

योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक आदर्श समाज व्यवस्था निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध आवाज ही नहीं उठाई, अपने राजनीतिक जीवन के अनेक उदाहरणों से समाज को सक्रिय प्रशिक्षण भी दिया। वे समता के पोषक हैं, इसलिये उन्होंने पूरी शक्ति के साथ जाति के दंश, प्रथा एवं विसंगति पर प्रहार कर मानवीय एकता का स्वर प्रखर किया। उनके शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता दी, जिससे राज्य में अपराध और अराजकता पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया। 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास' की नीति पर चलते हुए उन्होंने गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू कीं। बुनियादी ढांचे के विकास, धार्मिक स्थलों के पुनरोद्धार, निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन में भी उनके प्रयास उल्लेखनीय हैं। उनकी सकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज तेजी से विकासशील राज्यों में गिना जाने लगा है और जातिवाद, भ्रष्टाचार और असुरक्षा की छवि से बाहर निकलकर एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उनकी ताजा पहल समाज को बताती है कि नई पीढ़ी को जाति नहीं, योग्यता और नैतिकता के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। यह निर्णय राजनीतिक दलों के लिए भी चेतावनी है कि उन्हें जातिगत समीकरणों की राजनीति छोड़कर राष्ट्रहित और जनहित की राजनीति करनी होगी। जाति, रंग, भाषा आदि के मद से सामाजिक एवं राजनीतिक विक्षोभ पैदा होता है, इसीलिये यह पाप की परम्परा को बढ़ाने वाला पाप है। इसके कारण राष्ट्रीयता को भूल कर जातिगत संकीर्णताओं को लोग आगे बढाते रहे हैं, एक जाति के लोग मजबूत होने के बाद वे अपनी जाति को लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। यह धारणा भी बढती.रही है कि सबको अपनी जाति की चिंता करनी चाहिए। यह भ्रांति भी फैल रही है कि अपनी जाति के लोग या अधिकारी या नेता ही अपनी जाति के समुदाय या लोगों की मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। ऐसी तमाम सामाजिक व प्रशासनिक खामियों एवं विडम्बनाओं से उबरने की जरूरत योगी सरकार ने महसूस की है। अन्यायी के खिलाफ बिना जाति देखे खड़ा होना चाहिए। संविधान की भी मंशा यही है कि हर नागरिक को अपने समाज की ताकत बनकर आगे बढ़ना चाहिए और ध्यान रहे, यह समाज मात्र एक जाति आधारित न रहे। हर जाति महत्वपूर्ण है और सबका विकास हो, पर जाति आधारित लगाव या राजनीति का दिखावा खत्म होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार का यह कदम भारतीय समाज को जातिवाद की जंजीरों से मुक्त कराने का बड़ा अवसर है। यह केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है। अब आवश्यकता है कि अन्य राज्य भी इसे अपनाएं और भारत को सच्चे अर्थों में समानता, न्याय और बंधुत्व की धरती बनाएं।

भारत के प्रधानमंत्री को पूरा विश्व दे रहा सम्मान और विपक्ष कर रहा अपमान

बिहार विधानसभा चुनाव -2025 को लेकर राजनैतिक दलों की गतिविधियां तीव्र हो चली हैं । यद्यपि अभी वहां चुनाव होने में दो माह से अधिक का समय शेष है तथापि चुनावी घमासान चरम पर पहुंच गया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को ठीक करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर कराया तो राहुल बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकालने में लग गए जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सहित तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी शामिल हुए।

राहुल गांधी की यह यात्रा तो थी वोटर अधिकार रैली किंतु आगे बढ़ते हुए बन गई बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया बचाओ और उनको मतदाता बनाओ रैली। राहुल गांधी की बिहार में आयोजित वोटर अधिकार रैली में भारत के प्रति अपनेपन का गहरा अभाव रहा। तमिल नेता स्टालिन को बुलाकर

राहुल गांधी की यह यात्रा तो थी वोटर अधिकार रैली किंतु आगे बढ़ते हुए बन गई बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया बचाओ और उनको मतदाता बनाओ रैली। राहुल गांधी की बिहार में आयोजित वोटर अधिकार रैली में भारत के प्रति अपनेपन का गहरा अभाव रहा।

हिंदी भाषा का अपमान किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे व राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने पटना रैली में भारत व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित चुनाव आयोग के खिलाफ जी भरकर नफरत भरी बयानबाजी की और अपशब्द कहे। यात्रा अंतिम चरण तक पहुँचते पहुँचते इतनी जहरीली हो गई कि राहुल के करीबी नेताओं ने भरे मंच प्रधानमंत्री की माँ के लिए लिंगवाचक गालियों का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार राहुल गांधी अपना परमाणु बम प्रभावहीन होने बाद हाइड्रोजन बम की तलाश में हैं। वोटर अधिकार यात्रा अराजकता और राहुल गांधी व उनके समर्थकों की अनुशासनहीनता और अभद्रता के प्रदर्शन के कारण ही चर्चा में रही। जिस समय पूरा वैश्विक समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुनना और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाह रहा है, उनके नेतृत्व में एक नया वर्ल्ड आर्डर आकार ले रहा है उस समय राहुल गांधी -तेजस्वी यादव व अन्य नेताओं ने मोदी व उनकी मां तक का अपमान करने का कोई अवसर नही छोड़ा। राहुल गांधी के नेतृत्व वाला संपूर्ण विपक्ष बहुत ही ओछी प्रवृत्ति का उदाहरण प्रस्तुत करता रहा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़्गे व राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने पटना रैली में भारत व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित चुनाव आयोग के खिलाफ जी भरकर नफरत भरी बयानबाजी की और अपशब्द कहे।

बिहार के दरभंगा जिले में कांग्रेस के मंच से एक स्थानीय मुस्लिम नेता मोहम्मद रिजवी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहे, उससे भी आश्चर्यजनक बात यह रही कि राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ता की उस शर्मनाक हरकत के लिए सार्वजनिक माफी तक नहीं मांगी बल्कि अलग अलग तरह से उसका बचाव किया। वोटर अधिकार रैली का सारा प्रकरण अब प्रधानमंत्री मोदी व उनकी मां के अपमान की ओर झुक गया। प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान की चारों ओर निंदा हो रही है ।जो लोग वोट चोर के नारे से नायक बनने निकले थे अब उनके चेहरे पर हवाईयां उड़ती दिख रही हैं।

पीएम मोदी को 111वीं गाली व मां का अपमान अब विपक्ष पर भारी- हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों के नेताओं की गालियों को अपना हथियार बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की महिलाओं को एक कार्यक्रम में भोजपुरी में संबोधित करते हुए इसे केवल अपनी मां का नहीं अपितु देश की हर मां बहन और बेटी का अपमान बताया। प्रधानमंत्री मोदी का यह भावुक संबोधन सुनकर बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व वहां पर उपस्थित तमाम मातृशक्ति के आंखां में अश्रु आ गए। बिहार में भाजपा व राजग गठबंधन ने इसे लेकर सफलतापूर्वक पूर्ण बंद किया है। राजग गठबंधन की ओर से आयेजित बंद को बिहार में पूर्ण समर्थन मिल रहा है अनेक स्थानों पर महिला कार्यकर्ता ही बंद का आयोजन कर रही हैं।

इतिहास साक्षी है कि जब -जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे गए हैं या उनका सार्वजनिक अपमान किया गया है तब -तब उन्हें राजनैतिक लाभ हुआ है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तभी से कांग्रेस व विरोधी दलों के नेताओं में उन्हें अपशब्द कहने की होड़ लगी है। आज कांग्रेस का कोई नेता ऐसा नहीं बचा है जिसने उन्हें गाली न दी हो या फिर अपमानित न किया हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर से लेकर जहरीला सांप, नीच आदमी, रावण, भस्मासुर और वायरस तक कहा जा चुका है। दिसंबर 2017 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि, यह बहुत नीच किस्म का आदमी है इसमें कोई सभ्यता नहीं है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने मोदी बोटी बोटी काटने की बात कही थी। बेनी प्रसाद वर्मा ने पागल कुत्ता बताया था। एक समय था जब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देने की झड़ी लगा दी थी।

सोनिया और राहुल सहित कांग्रेस के 12 ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जमकर गालियां दी और हर गाली के बाद देश में जहां भी चुनाव हुए वहां का राजनैतिक वातावरण बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध निजी अपमानजनक टिप्पणी कांग्रेस को हमेशा नुकसान पहुंचाती है लेकिन यह बात राहुल गांधी व उनके सलाहकार समझ नहीं पा रहे हैं। राजनैतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां के अपमान से अब बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। प्रधानमंत्री मोदी व एनडीए समर्थक कार्यकताओं में अभूतपूर्व आक्रोष व्याप्त हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान एक मुस्लिम नेता ने किया है और राहुल गांधी ने केवल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ही वोटर अधिकार यात्रा निकाली है जिसका असर यह होगा कि अब वहां पर मतों का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होगा। बिहार की राजनीति में मातृशक्ति निर्णायक मतदाता है और नीतिश कुमार की सरकार में नारी शक्ति के हित में कई कार्य हुए हैं । उस पर मोदी जी की मां के अपमान से अब महिला मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग राजग गठबंधन की ओर झुक जाएगा। मां के प्रति अपमानजनक शब्द सुनकर प्रधानमंत्री मोदी का भावुक होना स्वाभाविक है। उनकी मां तीन वर्ष पूर्व नश्वर देह त्याग चुकी हैं, वे कभी राजनीति में भी नहीं रहीं ऐसी परिस्थिति में मां का अपमान कोई भी बेटा स्वीकार नहीं करेगा। यदि जिस दिन यह दुखद घटना घटी उसी दिन राहुल और तेजस्वी उसकी कड़ी निंदा कर माफी मांग लेते तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। राहुल गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अपने छुटभैये मुस्लिम नेता से प्रधानमंत्री और उनकी माँ को अपमानित कराकर ऐसा सेल्फ गोल किया है जिसकी भरपाई असंभव है।

लद्दाख के जेन-जेड क्रांति से सबक सीखे भारत, अन्यथा.....!

ऐसा इसलिए कि आप लद्दाख की इस घटना से लेकर नेपाल के हाल-फिलहाल के वाकये तक इनके द्वारा लिखी व बोली गई अनाप-शनाप बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। वास्तव में ये जाने-अनजाने में देश धर्म विरोधी तत्त्वों के हथियार बन रहे हैं।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जारी आंदोलन ने गत्व बुधवार को हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। इसके बाद लेह में प्रदर्शनकारी छात्रों की सुरक्षाबलों से झड़प हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 70 से ज्यादा घायल है। वहीं, प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी गई। चूंकि यह अतिवादी कार्रवाई है। इसलिए हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं, हालात को देखते हुए लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया। बिना मंजूरी के रैली और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। बताते चलें कि लद्दाख को राज्य का दर्जा

मुकुल पंडित

समेत कई मांगों पर सोशल ऐक्टिविस्ट सोनम वांगचुक विगत 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। लिहाजा, उनकी मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को बंद बुलाया। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर लोगों से लेह हिल काउंसिल पहुंचने की अपील की गई। जिसके बाद गत बुधवार को सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे। इसी दौरान हिंसा हुई। सरकारी सूत्रों ने कहा कि हिंसा में राजनीति से प्रेरित साजिश की बूआ रही है।

वहीं, केंद्र सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सोनम वांगचुक के उकसाऊ बयानों से यह हिंसा भड़की है। इससे पहले वांगचुक ने हिंसा पर दुख जताते हुए अनशन तोड़ दिया। उन्होंने इन घटनाओं के लिए जेन-जेड (1997 से 2012 के बीच जन्म लेने वाली पीढ़ी) की हताशा को जिम्मेदार ठहराया और शांति की अपील की। उल्लेखनीय है कि प्रदर्शनकारियों की 4 अहम मांगें हैं- लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्वोत्तर की तरह संवैधानिक सुरक्षा, करगिल, लेह की अलग-अलग लोकसभा

सीट और सरकारी जॉब्स में में स्थानीय लोगों की भर्ती।

इससे स्पष्ट है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीन के हमदर्द राहुल गाँधी जो नेपाल-बंगलादेश की तरह पूरे देश में यही कुछ चाहते थे, के मनोरथ पूर्ण होने की तरफ बात बढ़ चली है। यदि शेष भारत में गृहयुद्ध भड़कता है तो इसके लिए इस देश में केवल विपक्षी दल, कथित सिविल सोसायटी और बाहरी शक्तियाँ, यथा- अमेरिकी डीप स्टेट तथा इस्लामिक अतिवादी संस्थाएं दोषी तो होंगी ही, साथ ही साथ इस बद से बदतर स्थिति के लिए कथित राष्ट्रभक्त हिंदू और सनातन धर्म प्रेमी लोगों का एक बड़ा तबका भी होगा जो उनके इशारे पर थिरकते हैं।

ऐसा इसलिए कि आप लद्दाख की इस घटना से लेकर नेपाल के हाल-फिलहाल के वाकये तक इनके द्वारा लिखी व बोली गई अनाप-शनाप बातों से अंदाजा लगा सकते हैं।वास्तव में ये जाने-अनजाने में देश धर्म विरोधी तत्त्वों के हथियार बन रहे हैं। यह गम्भीर बात है। इससे संवैधानिक सफलता भी संदिग्ध हुई है। सच कहूं तो भारत के अतिसंवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश 'लद्दाख' से जेन-जेड क्रांति का जो आगाज दिखाई-सुनाई पड़ा है, यह हमें समय रहते ही सावधान करने के लिए काफी है। यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। चाहे सम्बन्धित सेना हो या सिविल व पुलिस प्रशासन, यदि उनके द्वारा अमेरिकी खुफिया इकाई सीआईए द्वारा प्रोत्साहित इस कथित जेड-जेन क्रांति को सख्ती पूर्वक नहीं कुचला गया तो उनका भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा!

बेहतर होगा कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों को अविलंब कैद करके उन्हें आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उनके कुकर्मों से धन-जन की हानि हुई है, अन्यथा भारतीय लोकतंत्र में भी एक गलत ट्रेंड स्थापित हो जाएगा। एशियाई लोकतंत्र की सफलता पर सवाल उठेंगे। ऐसा इसलिए कि पश्चिमी लोकतंत्र खूनी लोकतंत्र है, पक्षपाती डेमोक्रेसी है। जिसका मकसद दुनिया भर में लोकतांत्रिक जनभावना मजबूत करना नहीं, बल्कि अपने आर्थिक व साम्राज्यवादी लाभ के लिए दुनिया में कठपुतली सरकार कायम करना है।

यही वजह है कि जेन-जेड जैसी कथित क्रांति से हो रहे सत्ता परिवर्तन और बन रही कठपुतली सरकारों को दुनियावी लोकतंत्र की सफलता के लिहाज से उचित नहीं समझा जा सकता है। इसलिए

बताते चलें कि कथित पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाख में चल रहा प्रदर्शन जिस प्रकार से हिंसक हो गया और भाजपा के कार्यालय तक को निशाना बनाया गया, उसमें भाड़े के उत्पाती शामिल नहीं हैं तो क्या हैं?

लद्दाख घटनाक्रम के बाद भारत को ठोस और प्रभावी कदम उठाने ही होंगे और इससे अपने पड़ोस को भी लाभान्वित करने की सद्भावना रखनी होगी। कहना न होगा कि 2014 की सनातन युवा क्रांति के बाद बनी भाजपा नीत मोदी सरकार की सफलता से ही भारत, अमेरिका-चीन और अरब देशों के निशाने पर है। इसलिए श्रीलंका, अफगानिस्तान, बंगलादेश, नेपाल आदि में जो जेन-जेड क्रांति हुई, उसका मकसद भारतीय राजनेताओं और सेना के धैर्य की परीक्षा लेना था। जब हम लोकतंत्र की पैरोकारी में मजबूती पूर्वक विफल रहे तो लद्दाख जेन-जेड क्रांति हमें मुबारक कर दिया गया।

सवाल है कि यह भी प्रयोग केरल, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर के बजाय बौद्ध धर्म बहुल लद्दाख में करवाया गया ताकि बौद्धों के प्रति हिंदुओं के मन में नफरत पैदा हो और चीन-भारत व तिब्बत-भारत के रिश्तों में पलीता लगे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ होता तो बेहतर होता। लेकिन चरमपंथियों और हिंसकों को कुचलने के बजाय स्थानीय सेना व प्रशासन द्वारा ऐसे अराजक तत्वों से बात करने से समकालीन लोकतंत्र के प्रति गलत संदेश गया है।

लिहाजा, अविलंब इसकी भरपाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, रूस और चीन आदि के साथ मिलकर अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा असहयोग मिलने पर भारत की सेना को ही इन पर आक्रमण करके इन्हें भारतीय भूभाग में मिला लेना चाहिए। इसके साथ ही पश्चिमी देशों व ब्रिक्स देशों जैसे लोकतंत्र के कथित दरिंदों को ग्लोबल साउथ के समक्ष बेनकाब करने की स्पष्ट रणनीति अख्तियार करनी चाहिए।

कहने का तातपर्य यह कि विधि के शासन को बहाल करने के लिए भारत व उसके पड़ोसी देशों की सेना को आपसी सांठगांठ करके व स्थानीय सिविल व पुलिस प्रशासन को भरोसे में लेकर निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। इस दिशा में हर तरह की कुबार्नी के लिए भी तैयार रहना चाहिए और किसी तरह के 'कत्लेआम' से गुरेज नहीं करना चाहिए। अन्यथा भारत विकास और सुशासन की रेस में पिछड़ जाएगा।

समकालीन जेन-जेड की हिंसक प्रवृति को

देखते हुए लोगों को आशंका है कि जी-7 और ब्रिक्स के कतिपय चतुर सुजान देश यही अराजकता चाहते हैं, ताकि उनके गोला-बारूद की खपत बढ़े। इसी की आड़ लेकर वे दुनियावी प्राकृतिक संसाधनों को लूट सकें। इसलिए भारत को अविलंब जिला स्तर पर अपनी तैयारी को धार दी जानी चाहिए, ताकि हिंसक व अराजक तत्वों को उनकी औकात में रखा जा सके। अन्यथा यह 'खूनी लोकतंत्र' भविष्य में अमेरिकी पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। बहरहाल ये अराजकता पैदा करके हथियार बेचेंगे और भारतीय उपमहाद्वीप भी अरब व खाड़ी देशों की तरह झुलसता रहेगा।

बताते चलें कि कथित पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाख में चल रहा प्रदर्शन जिस प्रकार से हिंसक हो गया और भाजपा के कार्यालय तक को निशाना बनाया गया, उसमें भाड़े के उत्पाती शामिल नहीं हैं तो क्या हैं? यह ठीक है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अगुआई में लंबे वक्त से यह मांग उठायी जा रही है और इसे लेकर केंद्र से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन, इस दौरान इस सोच का हिंसा का हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक दोनों है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि पूरे देश में एक सही संदेश जाए।

यह ठीक है कि सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35-ए के प्रावधान हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया था। तब सरकार ने वादा किया था कि हालात सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि 6 साल बाद लोगों का भरोसा और सब्र डगमगाने लगा है। फिर भी लेह में हिंसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे विदेशी ताकतों के हाथ की पड़ताल और जम्मू-कश्मीर सरकार की परोक्ष भूमिका की जांच होनी चाहिए।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि सोनम वांगचुक इस मुद्दे पर पिछले कई महीनों से आंदोलनरत रहे हैं। पिछले साल मार्च में भी वह 21 दिनों के आमरण अनशन पर बैठे थे। उसके बाद दिल्ली तक पदयात्रा निकाली। इस समय भी उन्होंने 15 दिनों का अनशन शुरू किया था, लेकिन एक दिन पहले दो लोगों की तबीयत बिगड़ी और हालात काबू से बाहर हो गए। यह हिंसा कतई उचित नहीं है।

चूंकि लेह में हुए प्रदर्शन को जेन-जेड का आंदोलन कहा जा रहा है। क्योंकि कुछ दिनों पहले यही पीढ़ी नेपाल में सत्ता बदल चुकी है। लेकिन, नेपाल और लद्दाख की तुलना कतई नहीं की जा सकती है। और न ही हिंसा को किसी भी तरह से जायज ठहराया जा सकता है। वैसे भी सोनम वांगचुक का पूरा आंदोलन अहिंसक रहा है। यहां तक कि सरकार से मतभेद होने पर भी उन्होंने बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ा है। लिहाजा, उनके समर्थन में खड़े युवाओं को इसे समझना चाहिए। क्योंकि विदेशी शह प्राप्त हिंसा से उनकी समस्या और अधिक जटिल हो जाएगी।

ऐसे में स्वाभाविक सवाल है कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है? भारत के प्रगतिशील लोगों की राय है कि इसके लिए लद्दाख के लोगों की चिंता पर संवेदनशीलता से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि उनमें यह डर है कि अगर शासन उनके हाथ में न रहा तो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होगा। चूंकि छठी अनुसूची, स्वायत्तता और स्वशासन के कुछ विशेष अधिकार देती है। इसलिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र की तरह ही लद्दाख को भी इस सूची के तहत सुरक्षित किये जाने की पहल अविलंब की जानी चाहिए।

बताया गया है कि केंद्र सरकार और आंदोलन में शामिल लेह एपेक्स बॉडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच आगामी 6 अक्टूबर को बातचीत प्रस्तावित है। इसलिए लोगों में यह विश्वास पैदा करना जरूरी है कि फैसलों में लद्दाख के हितों का ख्याल रखा जाएगा। इसका सबसे बेहतर तरीका पारदर्शिता है। वहीं, जनता को भी समझना होगा कि सरकार के लिए हर मांग मानना और तुरंत मानना संभव नहीं होता है। इसके लिए भी कमेटी गठित करनी पड़ती है।

वक्फ संशोधन अधिनियम में हुए सुप्रीम संशोधन के मायने

ब्रिज पंवार

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन उसके कुछेक प्रावधानों में विधिसम्मत और तर्कसंगत संशोधन किया है या फिर पूरी तरह से उन पर रोक लगा दी है। इसलिए वक्फ संशोधन अधिनियम में हुए सुप्रीम संशोधन के मायने समझना बहुत जरूरी है। लोगों को उम्मीद है कि कोर्ट के इस ताजातरीन फैसले से वे आशंकाएं दूर हो जाएंगी, जो इस नए कानून को लेकर इससे पहले जताई जा रही थीं। चूंकि कोर्ट का यह निर्णय संविधान के अनुरूप है, इसलिए दोनों पक्षों ने इसे मान लिया है। यह एक शुभ लक्षण है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए संशोधन महत्वपूर्ण और जरूरी हैं, क्योंकि इनमें संविधान की भावनाओं का भी ख्याल रखा गया है। इसलिए इसके परिवर्तित मायने राष्ट्रीय एकता के लिहाज से अहम हैं।

पहला, कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था, बताया गया है। हालांकि यह रोक तभी तक लागू रहेगा जब तक राज्य सरकारें इसके लिए अलग से नियम नहीं बना देतीं। चूंकि यह शर्त मनमानी हो सकती थी, इसलिए अदालत ने इसे स्थगित कर दिया है। समझा जाता है कि वक्फ करने के लिए न्यूनतम 5 बरसों तक इस्लाम का अनुयायी होने के प्रावधान पर तब तक रोक रहेगी, जब तक राज्य सरकारें इसके सत्यापन के लिए नियम नहीं बना लेती। चूंकि देश में धर्म व्यक्तिगत मामला है और यह जरूरी नहीं कि कोई नागरिक अपनी धार्मिक पहचान का सार्वजनिक प्रदर्शन करे। इसलिए यह तय करना कि कोई किसी धर्म को कब से मान रहा है, बेहद जटिल है। राज्य सरकारों से उम्मीद है कि इस बारे में नियम बनाते समय वे सभी पहलुओं का ध्यान रखेंगी और ज्यादा संवेदनशीलता बरतेंगी।

दूसरा, कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया है कि जिला कलेक्टर को यह फैसला देने का अधिकार नहीं है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट अंतिम निर्णय न कर ले। इससे कलेक्टर की शक्ति सीमित हुई है और मनमानी पर रोक लगी है। यह एक अहम संशोधन है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने वक्फ संपत्ति जांच के प्रावधानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नामित अधिकारी की आंशिक रूप से रिपोर्ट के आधार पर ही किसी प्रॉपर्टी को गैर-वक्फ नहीं माना जा सकता। समझा जाता है कि अदालत ने संपत्ति अधिकार तय करने की ताकत जिलाधिकारी को देने को संविधान में की गई व्यवस्था शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ माना है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि लोकतंत्र के तीनों अहम अंगों- विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का संतुलन बना रहे। एक पक्ष की ओर पलड़े का थोड़ा भी झुकाव व्यवस्था के संतुलन को बिगाड़ देगा। तीसरा, वक्फ बोर्ड में सदस्यों की संख्या और गैर-मुस्लिम सदस्यों की सीमा में संशोधन भी कुछ हद तक सुरक्षित की गई है, लेकिन कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर स्थगन लगाया है। लिहाजा लोगों को उम्मीद है कि अब उनकी सरकार अन्य धर्मों के लिए भी इसी तरह के कानून लाएगी व उसका अनुपालन का निर्णय करेगी। चतुर्थ, कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को शक्ति के 'मनमाने' प्रयोग को रोकने के लिए अस्थायी रूप से स्थगित किया है, जिसमें वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और बुजुर्गों का धर्म पालन जैसे मुद्दे शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के कई बिंदुओं पर विपक्ष को गहरी आपत्ति थी। इसे लेकर दोनों सदनों में और सड़क पर भी काफी हंगामा हुआ। इस मामले की गंभीरता और उसके असर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिम्मेदारी भरा है। यूँ तो इस बाबत दायर याचिका में पूरे कानून को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे नहीं माना। इस तरह के कदम बेहद दुर्लभ मामलों में उठाए जाते है और इनका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। देखा जाए तो इस मायने में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया, और यह भी ध्यान रखा कि विधायिका के साथ सीमाओं का अतिक्रमण न हो। इसलिए उसने समझदारी पूर्वक बीच का रास्ता निकाला है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले में बेहद संतुलित नजरिया अपनाया है। सच कहा जाए तो कोर्ट का यह फैसला वक्फ कानून में संतुलित नजरिया को अधिक न्यायसंगत और संवैधानिक बनाने की दिशा में संकेत देता है। साथ ही इसके मार्फत सरकारी शक्तियों और व्यक्तिगत अधिकारों का संतुलन बनाने का प्रयास भी किया गया है। कोर्ट के इस फैसले से संबंधित कुछ नियम और प्रावधान तभी तक लागू नहीं होंगे, जब तक इस बारे में अधिक स्पष्ट नियम और निर्देश नहीं बन जाते। इस तरह से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जबकि पूरे कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है।

आखिर कौन कर रहा है सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश ?

प्रवीण सिंह कुशवाहा

उत्तर प्रदेश के कानपुर में बारावफात जुलूस के दौरान लगे, 'आई लव मोहम्मद' बोर्ड से शुरू हुआ विवाद अब देशभर में फैल रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, बरेली, लखनऊ, महराजगंज, जालौन से लेकर कैसरगंज समेत कई शहरों में मुस्लिम समाज अत्यंत उग्रता के साथ जुलूस निकाल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बहुत ही सघन मुस्लिम बहुल इलाके में भी 'आई लव मोहम्मद' लिखा बैनर टांगा गया है जिसके कारण स्थानीय स्तर पर तनाव अनुभव किया गया। इन जुलूसों में कई जगह पुलिस से टकराव और पथराव भी हो रहा है। मुस्लिम समाज के लोग व मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में संलिप्त रहने वाले लोग इसे मुस्लिम समाज का जेन-जी आंदोलन कहकर आग में घी डालने का कुत्सित प्रयास करते नजर आ रहे हैं जो तनाव को और बढ़ा रहा है। सोची समझी रणनीति के अंतर्गत इस आंदोलन में नाबालिग बच्चों को आगजनी और पुलिस पर पथराव करने के लिए आगे किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश से शुरू हुयी ये अराजकता अब उत्तराखंड के काशीपुर और तेलंगना के हैदराबाद समेत देश के कई शहरों में पहुँच गई है। आइ लव मोहम्मद के समर्थन में उत्तराखंड में पुलिस बल पर सीधा पथराव तथा हमला किया गया, हमले में जिसमें महिला पुलिस कर्मी भी अभद्रता और मार पीट का शिकार हुयीं। पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ दी गयीं। यही हाल गुजरात के गोधरा शहर में भी हुआ और महाराष्ट्र के नागपुर में भी। इन प्रदर्शनों के दौरान 'सिर तन से जुदा' आरै लब्बैक-लब्बैक जैसे बेहद आक्रामक और आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं।

इस पूरे विवाद की पटकथा उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुई। कानपुर के रावतपुर में बारावफात जुलूस निकाला जा रहा था। जिस मार्ग पर जुलूस निकाला जा रहा था उसी रास्ते पर एक जगह "आई लव मोहम्मद" का साइन बोर्ड लगा दिया गया। इसको लेकर हिंदू पक्ष ने विरोध किया और आरोप लगाया कि यहां नई परंपरा शुरू की जा रही है। दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता देखकर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और किसी प्रकार से मामला यह कहकर शांत करवाया कि नियम है कि जुलूस में किसी तरह की नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। किन्तु बारावफात के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने नई परंपरा डालते हुए परंपरा वाली जगह पर ही टेंट और साइन बोर्ड फिर से लगवा दिया।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि, 'आई लव मोहम्मद'

को लेकर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इस बीच संभवतः पूर्व नियोजित साजिश के अनुसार कानपुर में मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष पर आरोप लगाया कि उसने साइन बोर्ड को फाड़ दिया था। वहीं हिंदू पक्ष ने इसका खंडन करते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष के जुलूस में शामिल लोगों ने हिन्दुओं के धार्मिक पोस्टर फाड़े। पुलिस के बीच-बचाव के बाद ऐसा लगा कि अब मामला शांत हो गया है। बाद में कानपुर पुलिस ने बारावफात के जुलूस के दौरान 'आई लव मोहम्मद' नाम का एक नया बोर्ड बनाकर नई परंपरा शुरू करने और सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने के लिए मुकदमा दर्ज किया।

इस बीच पहले से तैयार बैठे एआईएमआईएम नेता और सांसद असदुददीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर कानपुर पुलिस को टैग करते हुए एक पोस्ट लिखा कि, "आई लव मोहमद" कहना जुर्म नही है अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर हैं। ओवैसी ने जिस पोस्ट को लेकर कोट किया था उसमें दावा किया गया था कि मुस्लिम पक्ष की ओर से कथित तौर पर नई परंपरा शुरू करने को लेकर पुलिस ने मुकदमा कर दिया है। इस बात की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि ओवैसी की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहों का बाजार गर्म होता गया और अब यह आग देश के अनेकानेक हिस्सों में फैलती जा रही है।

तमाम कट्टरपंथी और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले तत्व इस आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो और कमेंट पोस्ट करके तनाव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह सब कुछ उस समय हो रहा है जब हिन्दू पर्वो की नवरात्र से देवदीपावली तक एक लंबी श्रृंखला चलने वाली है।

इन सभी घटनाओं का पैटर्न लगभग एक ही जैसा नजर आ रहा है। बरेली के जखीरा मुहल्ले में 'आई लव मोहम्मद' लिखे कई पोस्टर लगे थे। इंस्पेक्टर सुभाष कुमार ने बताया कि भीड़ होने की सूचना पर, वे पहुंचे तो पाया कि वहां इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के महासचिव डा. नफीस खान भी थे। पुलिस के पहुंचने पर नफीस खान ने वहां पर उपस्थित लोगों को घर जाने के लिए कह दिया किंतु बाद में इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ उसमें डा.नफीस कुछ लोगों से कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैंने इंस्पेक्टर को 'बहुत अपशब्द कहे। मैंने कहा कि, 'हाथ काट लूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा'। जांच मे पता चला है कि पुलिस के मोहल्ले से लौटने

के बाद नफीस ने भीड़ को भड़काने का प्रयास किया। नफीस बरेली में मौलाना तौकीर रजा खां की पार्टी आईएमसी के महासचिव हैं।

सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि इन जुलूसों में 10 साल से कम आयु के लड़कों तथा औरतों द्वार उग्र प्रदर्शन कराया जा रहा है। उन्नाव में

कानपुर के रावतपुर में बारावफात जुलूस निकाला जा रहा था। जिस मार्ग पर जुलूस निकाला जा रहा था उसी रास्ते पर एक जगह "आई लव मोहम्मद" का साइन बोर्ड लगा दिया गया। इसको लेकर हिंदू पक्ष ने विरोध किया और आरोप लगाया कि यहां नई परंपरा शुरू की जा रही है।

हिंसक उपद्रव का नेतृत्व महिलाओ व बच्चो ने किया। बुर्कानशीं महिलाओं ने ही पुलिस बल पर पत्थर बरसाये ओर नाबालिगों ने 'सर तन से जुदा' के नारे लगाकर माहौल खराब किया। कठिनाई यह है कि हमारे देश के संविधान में नाबालिगों को केवल सुधार गृह भेज दिया जाता है और महिलाओं की प्रायः जल्दी गिरफ्तारी नही होती। वहीं दूसरी ओर तथाकथित संविधान रक्षक मुस्लिम तुष्टिकरण का खेल प्रारंभ कर देते हे। इन सभी उपद्रवियों को पता है कि उन्हें सभी छद्म धर्मनिरपेक्ष दलों का खुला समर्थन प्राप्त है। नाबालिगों को सोच समझ कर केवल इसलिए शामिल किया जा रहा है क्योंकि वह आसानी से छूट जाएंगे और सजा भी बहुत कम होगी।

भारत में सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति पोस्टर बैनर लगाना गैरकानूनी है किंतु सभी लोग इसका उल्लंघन करते हैं। पुलिस का कहना है कि यह आंदोलन गुमराह करने वाला है। मुस्लिम तुष्टिकरण में संलिप्त नेता इस आंदोलन को अल्पसंख्यकों के दमन से उपजा आक्रोष बता रहे हैं और भाजपा व हिंदू संगठनों को दोष दे रहे हैं। एक पार्टी के प्रवक्ता तो तुष्टिकरण में इतने आगे बढ़ गए कि आंदोलन सम्बन्धी एफआईआर को ही संविधान विरोधी कृत्य बताने लगे। विगत दिनों बहराइच में एआईएमआईएम के नेता द्वारा स्थानीय महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान करने के कारण भी तनाव उत्पन्न हो गया था।

इस प्रकार के तनाव उत्पन्न करने का प्रयास उस समय किया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। योगी जी को अच्छी तरह से पता है कि उपद्रवियों व दंगाइयो से किस प्रकार निपटा जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता को सरकार व योगी जी की रणनीति पर पर पूरा भरोसा है। यहां की पुलिस सतर्क भी है और कड़क भी। उत्तर प्रदेश प्रशासन इस आंदोलन की जड़ तक जाएगा और षड्यंत्रकारियों को ढूंढ निकालेगा।

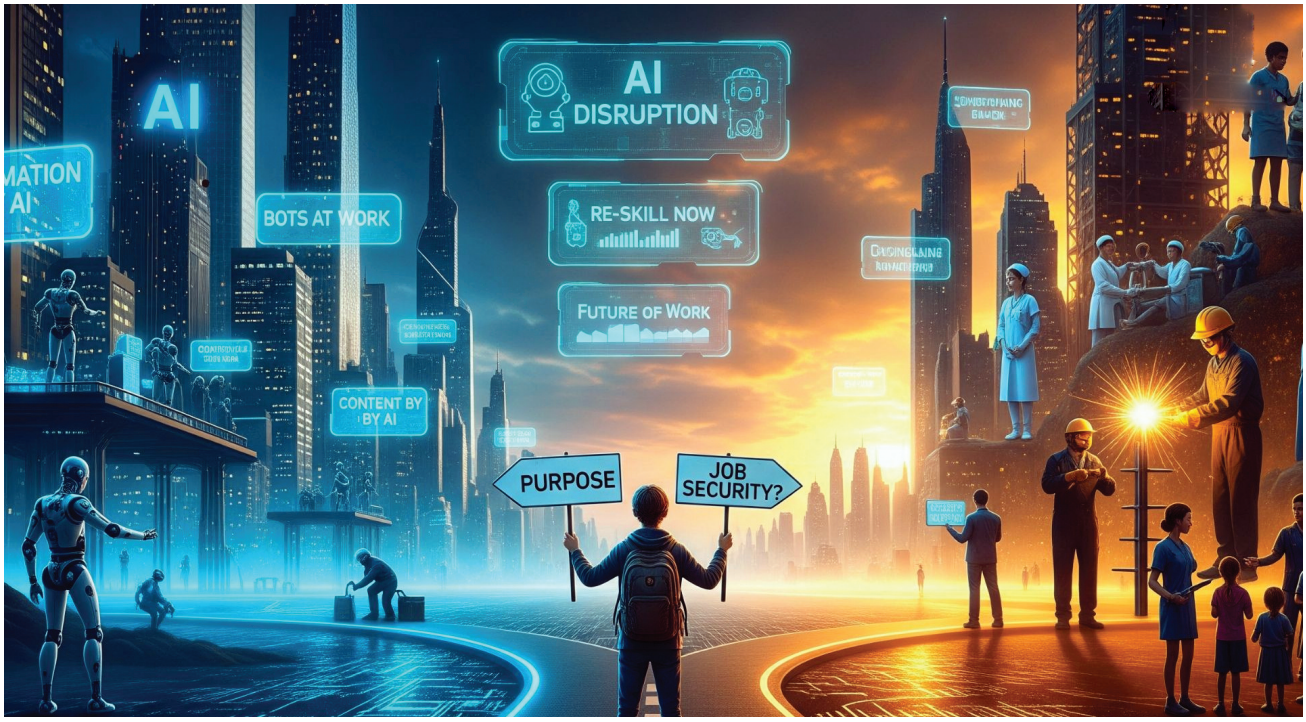

एआई का विस्तार या नौकरी का संकुचन एक बड़ी चुनौती

संजय बैंसला

एआई और ऑटोमेशन केवल तकनीक नहीं हैं, वे कार्य संस्कृति, संगठन संरचना और मानव संसाधन नीति को मूल रूप से बदल रहे हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार, एआई से प्रेरित उत्पादकता और लागत में कटौती की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

भारत जैसे युवाओं वाले और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश में तकनीकी विकास के प्रति उत्साह हमेशा गहरा रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी तकनीकें समाज, राष्ट्र और अर्थव्यवस्था में तीव्र बदलाव की सारथि बनी हैं। हर वर्ग और क्षेत्र ने इस परिवर्तन को आशा एवं सकारात्मकता के साथ अपनाया है, इस उम्मीद में कि तकनीकी तरक्की के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। लेकिन हाल ही में आईटी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा 12,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया और इसे बड़ा झटका दिया है। निस्संदेह, छंटनी का यह फैसला आईटी क्षेत्र में आसन्न संकट की आहट को ही दर्शाता है। छंटनी बाबत टीसीएस की दलील है कि इन नौकरियों में कटौती कौशल की कमी और अपने विकसित होते व्यावसायिक मॉडल में कुछ कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करने में असमर्थता के चलते की गई है। हालांकि, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का दावा है कि इस कदम के पीछे एआई से प्रेरित उत्पादकता वृद्धि नहीं है। यह संख्या कंपनी के कुल कार्यबल का लगभग 2 प्रतिशत है, और मुख्यतः मध्यम और वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों को प्रभावित करेगी।

एआई और ऑटोमेशन केवल तकनीक नहीं हैं, वे कार्य संस्कृति, संगठन संरचना और मानव संसाधन नीति को मूल रूप से बदल रहे हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार, एआई से प्रेरित उत्पादकता और लागत में कटौती की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर, एमेजोन ने 30,000 सॉफ्टवेयर एप्लिकेशनों को एआई की मदद से मात्र छह महीनों में अपग्रेड किया, जो कार्य सामान्यतः डेवलपर्स को एक वर्ष लगता। इससे कंपनी को लगभग 250 मिलियन डॉलर की बचत हुई। इसी प्रकार, माइक्रोसोफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों में कोडिंग का 20 से 50 प्रतिशत कार्य एआई से कराया जा रहा है। भारत में एआई का प्रसार अभी अमेरिका या यूरोप की तुलना में सीमित है, लेकिन इसकी गति तीव्र है। देश के स्टार्टअप और आईटी क्षेत्र में छंटनियों की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, केवल वर्ष 2025 के शुरूआती पांच महीनों में भारत में 3600 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया, जिसमें एआई आधारित लागत नियंत्रण एक प्रमुख कारण

रहा। यह स्पष्ट करता है कि एआई के कारण दोहराव वाले कार्यों की उपयोगिता घट रही है और उनकी जगह स्मार्ट तकनीक ले रही है। मौजूदा समय में यह कदम लागत-अनुकूलन पहलों के चलते अन्य आईटी सेवा कंपनियों में भी छंटनी को बढ़ावा दे सकता है। इसमें दो राय नहीं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कारोबार के नियमों में मौलिक बदलाव के चलते, भविष्य के लिये तैयार रहना हर व्यावसायिक उद्यम के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। इस नई हकीकत को देखते हुए, अनेक सवाल सबसे ज्यादा विचलित करने वाले बनकर उभर रहे हैं कि क्या यह तकनीकी बदलाव अनिवार्य रूप से कर्मचारियों की कीमत पर होना चाहिए? एआई युग में नौकरी की अनिश्चितता क्या तकनीक विकास के नाम पर विस्थापन नहीं है? छंटनी की चपेट में युवाओं का भविष्य क्या तकनीकी प्रगति के नाम पर मानव श्रम पर आघात नहीं है? क्या स्मार्ट मशीनें के दौर में भारत में रोजगार को नई चुनौती और इंसानों को हताशा में धकेलना नहीं है? एआई का विस्तार यानी नौकरी का संकुचन क्या भारत के लिए बड़ी चेतावनी की घड़ी बन रहा है?

इन प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी का संकट किसी से छिपा नहीं है। देश में श्रमबल का कौशल विकास धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में आईटी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। लेकिन टीसीएस के इस फैसले से आईटी पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे उन लाखों छात्रों और डिग्री लेकर निकल रहे उत्साही इंजीनियरों में निराशा व्याप्त होगी। भारत में बढ़ता रोजगार संकट केंद्र सरकार से निरंतर हस्तक्षेप की मांग करता है। हाल ही में हरियाणा में हुई एक परीक्षा में लाखों युवाओं की भागीदारी इस बात का संकेत है कि रोजगार की मांग कितनी व्यापक और अवसर कितने सीमित हैं। देश ही नहीं, दुनिया में रोजगार का संकुचन एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। गोल्डमैन सोच्स की रिपोर्ट के अनुसार, एआई और ऑटोमेशन के चलते दुनिया भर में लगभग 300 मिलियन नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। विश्व आर्थिक मंच का आकलन है कि 2030 तक 92 मिलियन नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन उसी अवधि में 170 मिलियन नई नौकरियां भी पैदा होंगी। यह एक दोधारी तलवार है, जो बदलेगा, बचेगा; जो रुकेगा, वो हाशिए पर जाएगा।

टीसीएस का दावा है कि छंटनी का निर्णय भविष्य की जरूरतों के अनुसार संगठन को ढालने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी का ध्यान एआई में निवेश, नए बाजारों में प्रवेश, ग्राहक अनुभव सुधार और कार्यबल मॉडल के पुनर्गठन पर केंद्रित है। हालांकि, यह तर्क उन हजारों कर्मचारियों की व्यथा को शांत नहीं कर सकता जिनकी आजीविका पर इसका सीधा प्रहार हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से न केवल कंपनी के भीतर बल्कि समूचे आईटी क्षेत्र में आशंका, आक्रोश एवं अनिश्चितता का माहौल बन गया है। खासकर युवाओं और आईटी की पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों के लिए यह एक मानसिक झटका है। तकनीकी शिक्षा में दाखिले बढ़ रहे हैं, लेकिन रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। यह असंतुलन देश की सामाजिक स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें बताती हैं कि विश्व स्तर पर लगभग 40 प्रतिशत नौकरियां एआई के कारण जोखिम में हैं। भारत में अनुमान है कि 2025 तक 12-18 मिलियन नौकरियां एआई आधारित ऑटोमेशन के चलते प्रभावित हो सकती हैं, विशेषकर आईटी और बीपीओ क्षेत्रों में। एटेमबर्ग के संस्थापक के अनुसार, भारत में 40-50 प्रतिशत व्हाइट कॉलर नौकरियां एआइ से प्रभावित होने के कगार पर हैं, जिससे देश के मध्यवर्ग की आर्थिक स्थिरता को गहरा झटका लग सकता है।

टीसीएस की छंटनी ने बेरोजगारी के दौर में बड़ी हलचल मचाई है, हालांकि आईटी और तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिले बढ़े हैं, लेकिन उनमें व्यावहारिक और भविष्य-उन्मुख कौशल की कमी है। यह असंगति ही भविष्य में अधिक छंटनियों का कारण बन सकती है। एआई हर भूमिका को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे पुनर्परिभाषित करेगा। जहां दोहराव और विश्लेषण की आवश्यकता है, वहां एआई प्रभावी होगा, लेकिन रचनात्मकता, सहानुभूति और निर्णय क्षमता जैसे गुणों में मानव की भूमिका बनी रहेगी। डॉक्टर, शिक्षक, वकील, पत्रकार जैसे पेशों में एआईएक सहयोगी के रूप में कार्य करेगा, प्रतिस्थापन के रूप में नहीं। मेटा के प्रमुख एआई वैज्ञानिक यान लेकुन के अनुसार, 'एआई अधिकतर कार्यों का केवल एक हिस्सा ही कर सकता है, वह भी पूरी तरह परिपूर्ण नहीं। मानव श्रमिकों का सीधा प्रतिस्थापन संभव नहीं है।'

निश्चित तौर पर एआई और तकनीकी बदलाव अपरिहार्य हैं। सवाल यह है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं? इसके लिए तीन प्रमुख कदम जरूरी हैं, पहला पुनःकौशल और सतत शिक्षा यानी कार्यबल को भविष्य के अनुरूप प्रशिक्षित करना होगा। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई एथिक्स, सॉफ्ट स्किल्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण अनिवार्य बनाना होगा। दूसरा नीतिगत समर्थन यानी सरकार को एआई नीति, डिजिटल समावेशन और श्रमिक सुरक्षा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने होंगे। रोजगार खोने वालों के लिए पुनर्वास योजनाएं और स्किल अपडेट कार्यक्रम आवश्यक हैं। तीसरा सांस्कृतिक और सामाजिक समायोजन यानी एआई को केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के रूप में भी देखा जाना चाहिए। इसे अपनाने में पारदर्शिता, विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाना होगा। तकनीकी बदलाव नई संभावनाएं लेकर आते हैं, लेकिन वे अनायास ही चुनौतियां भी खड़ी करते हैं। टीसीएस की छंटनी से जो संदेश मिलता है वह यही है कि एआई युग में केवल वही टिकेगा जो परिवर्तनशील रहेगा। अब समय आ गया है कि हम तकनीक को केवल उपकरण नहीं, बल्कि नीति और जीवनशैली का हिस्सा मानें। सतत सीखना, अनुकूलन और सामाजिक न्याय, यही तीन स्तंभ हैं, जो भारत को इस तकनीकी क्रांति में न केवल जीवित, बल्कि अग्रणी बना सकते हैं।

मोदी सरकार: नारी शक्ति का उदयकाल

भारत की आधी आबादी, जिसे लंबे समय तक घर की चौखट और सामाजिक परंपराओं में सीमित माना जाता था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। बीते दशक में तस्वीर पूरी तरह बदली है—ऐसे कानून बने जिन्होंने महिलाओं को बराबरी और गरिमा का अधिकार दिया, और ऐसी योजनाएँ आईं जिन्होंने मातृत्व को सुरक्षित कर बेटियों के सपनों को पंख दिए। यही वजह है कि आज नारी शक्ति केवल वोट नहीं, अब राष्ट्र की आवाज है । इसी यात्रा में 2023 का 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' स्त्री प्रतिनिधित्व को नई ऊँचाई देने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में अंकित हो गया है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं

अनिल वशिष्ठ

की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। यह बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा में स्त्री शक्ति को प्रतिष्ठित करने का है।

मोदी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए 'मिशन शक्ति' की शुरूआत की। इसके अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर, 247 महिला हेल्पलाइन और डिजिटल शिकायत पोर्टल जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। हिंसा झेलने वाली महिलाएँ अब कानूनी, चिकित्सीय और मानसिक सहयोग एक ही स्थान पर पा रही हैं, और यह भरोसा जगा है कि उनकी आवाज अब अनसुनी नहीं होगी। मुस्लिम महिलाओं को अन्यायपूर्ण परंपरा से मुक्त करने वाला 'तीन तलाक' विरोधी कानून इसी दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित हुआ। वहीं कामकाजी महिलाओं के लिए 'मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017' के अंतर्गत अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया तथा बड़े संस्थानों में शिशु गृह (क्रेच) की सुविधा अनिवार्य की गई। इन पहलों ने महिलाओं को सुरक्षा और गरिमा के साथ कार्यक्षेत्र में सक्रिय योगदान का अवसर प्रदान किया।

मोदी सरकार की नीतियों में 'बेटी बचाओ,

बेटी पढ़ाओ'नारी सशक्तिकरण का मर्मस्थ स्त्रोत रहा है, और हाल के आँकड़े इसकी गवाही देते हैं। 2014-15 में जहाँ 1000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ थीं, 2023-24 में यह अनुपात बढ़कर 930 हुआ और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की नामांकन दर 75.51% से बढ़कर 78% पहुँची। मार्च 2022 में 'कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव'से 1,00,786 बच्चियाँ स्कूल लौटीं। 2014-16 में मातृ मृत्यु दर 130 से घटकर 2018-20 में 97 रह गई और संस्थागत प्रसव 87% से बढ़कर 94% से अधिक हुआ–यह दशार्ता है कि सुरक्षित मातृत्व ही विकसित भारत की सच्ची पहचान है। राज्यों के अनुभव इस प्रगति को और भी सजीव बना देते हैं। उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की दर 51% से घटकर 45.9% रह गई और गंभीर एनीमिया 2.1% से घटकर 1.7% पर आ गया–यह आँकड़े मातृ स्वास्थ्य सुधार की गवाही देते हैं। इसी कड़ी में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10.33 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए, जिनमें से 8.34 करोड़ परिवार सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जिससे माताओं और बच्चों को धुएँ से मुक्ति मिली। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने करोड़ों शौचालयों ने ग्रामीण महिलाओं को खुले में शौच की विवशता से उबारकर उनकी गरिमा और स्वास्थ्य दोनों को संबल दिया। यह सब मिलकर नारी जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान की नई कहानी लिख रहे हैं।

आर्थिक स्वतंत्रता भी अब महिलाओं की शक्ति का दूसरा नाम बन चुकी है। मोदी सरकार के प्रयासों से 'स्टैंड अप इंडिया'और 'मुद्रा योजना'ने लाखों महिला उद्यमियों को कारोबार के लिए वित्तीय सहारा दिया, जबकि 'लाखपति दीदी'और 'ड्रोन दीदी'योजना ने ग्रामीण महिलाओं को तकनीक और स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी भारत की नई पहचान बना दिया है। मुद्रा योजना में महिलाओं की हिस्सेदारी 68% है और 2016 से 2025 के बीच प्रति महिला औसत ऋण ₹62,679 तक पहुँचा। स्टैंड-अप इंडिया में 80% से अधिक ऋण महिलाओं को मिले। उत्तर प्रदेश में मनरेगा में उनकी भागीदारी 35% से बढ़कर 45.05% और श्रम-बल में 14% से बढ़कर 36% हुई। वाराणसी की 1.38 लाख ग्रामीण महिलाएँ स्व-सहायता समूहों से आत्मनिर्भर बनीं, जिनमें कई ड्रोन पायलटिंग, कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। यह दशार्ता है कि महिलाएँ अब केवल योजनाओं की भागीदार नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की सशक्त धुरी बन रही हैं। डिजिटल इंडिया ने महिलाओं के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव लाया है। शहरी भारत की महिलाएँ स्मार्टफोन और इंटरनेट के सहारे बैंकिंग, ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान को सहज बना रही हैं, तो ग्रामीण भारत की 76% महिलाएँ मोबाइल का उपयोग कर रही हैं और आधी से अधिक अपने निजी फोन की स्वामिनी बन चुकी हैं। यही तकनीकी पहुँच उन्हें डिजिटल विपणन, पैकेजिंग और ई-कॉमर्स से जोड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर कर रही है। साथ ही, महिला हेल्पलाइन 181, एनसीडब्ल्यू 247 और पावर लाइन-1090 सुरक्षा और न्याय की त्वरित पहुँच देकर उनके आत्मविश्वास को और गहरा कर रही हैं। मोदी सरकार का यह डिजिटल सशक्तिकरण महिलाओं को समय और दूरी की सीमाओं से आजाद कर अवसरों की नई दुनिया थमा रहा है और उन्हें नवोन्मेषी बना रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में महिलाओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति में नया इतिहास रचा। अग्निपथ योजना के तहत 153 महिला अग्निवीरों ने बेलगावी से प्रशिक्षण पूरा किया और नौसेना ने लगभग 20% पद महिलाओं के लिए खोले। जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सात महिला बीएसएफ कर्मियों ने 72 घंटे तक मोर्चा सँभालकर साहस का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को हर माँ और बहन को समर्पित किया। साथ ही सेना का 'ऑपरेशन सिंदूर'एक सांस्कृतिक प्रतीक बना–जहाँ राष्ट्र रक्षा के साथ महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा का संदेश भी प्रतिध्वनित हुआ। सचमुच, अग्निवीर बेटियाँ अब सीमाओं पर देश की ढाल हैं और 'सिंदूर'वीरता का प्रतीक है।

बेशक चुनौतियाँ अब भी हैं और सामाजिक पूर्वाग्रह भी कायम हैं, पर अब नींव इतनी मजबूत है कि बदलाव अटल है। मोदी युग में महिलाओं की आवाज अब निर्णय और दिशा गढ़ती है; नारी केवल लाभार्थी नहीं, परिवर्तन की शिल्पकार और राष्ट्र निर्माण की धुरी बन चुकी है। यदि यही रफ्तार कायम रही, तो 2047 का विकसित भारत सचमुच नारी-निर्मित भारत होगा–जहाँ हर क्षेत्र में स्त्री शक्ति समानता, समृद्धि और नई संभावनाओं की मिसाल बनेगी।

मोदी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए 'मिशन शक्ति' की शुरूआत की। इसके अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर, 247 महिला हेल्पलाइन और डिजिटल शिकायत पोर्टल जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। हिंसा झेलने वाली महिलाएँ अब कानूनी, चिकित्सीय और मानसिक सहयोग एक ही स्थान पर पा रही हैं, और यह भरोसा जगा है कि उनकी आवाज अब अनसुनी नहीं होगी।

मणिपुर में विकास और शांति की एक नई भोर

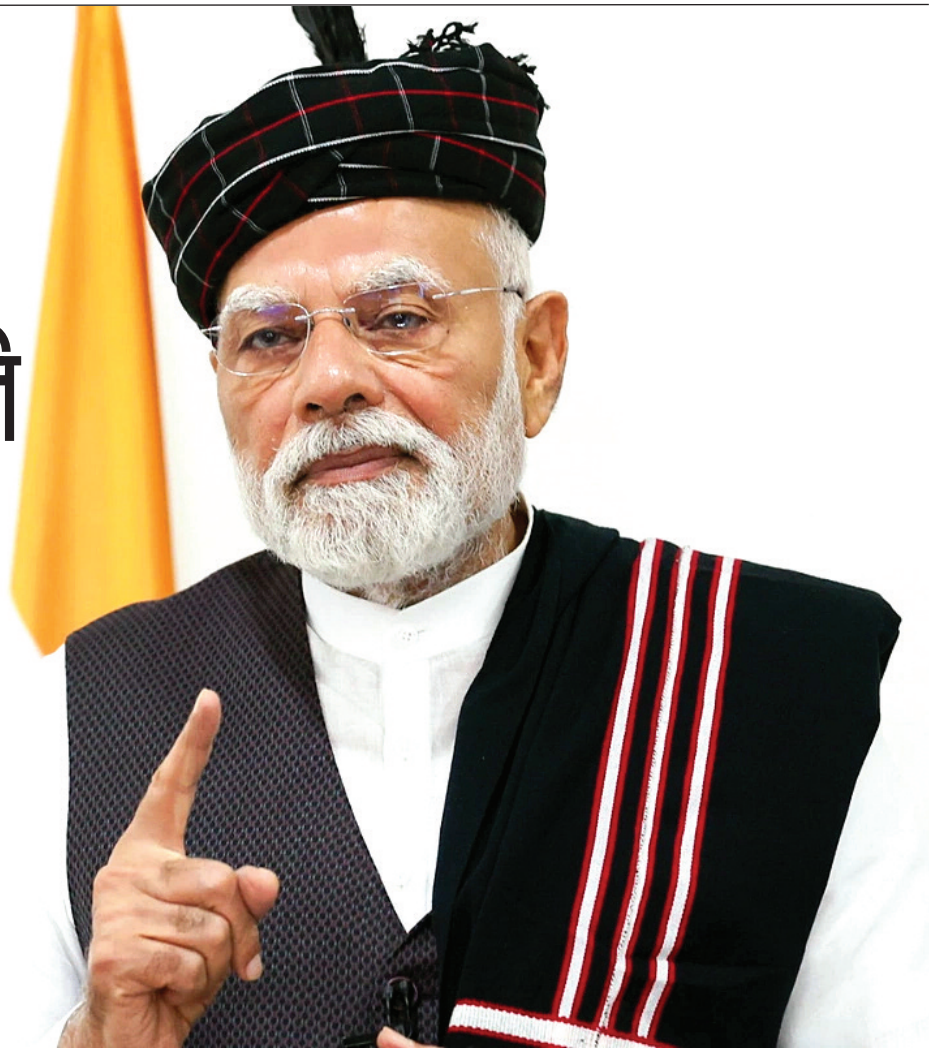

हरेन्द्र शर्मा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुकी बहुल हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित चुराचांदपुर के लिए 7,300 करोड़ रुपए से अधिक और मैतेई बहुल इंफाल के लिए 1,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करके यह संदेश देने का प्रयास किया कि सरकार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत उनके साथ है।

मई 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद मैतेयी और कुकी समुदायों के मध्य भड़की हिंसा से अब तक 260 लोग मारे जा चुके हैं तथा 60 हजार से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस संघर्ष के आरम्भ से ही भारत के सभी विपक्षी दल निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सरकार पर हमलावर थे, उनका एक ही प्रश्न था कि मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे ? मणिपुर को लेकर संसद ठप रखी गई। मणिपुर में महिलाओं पर हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की खंडपीठ ने मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां का दौरा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी व अन्य नेतागण अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए मणिपुर के हालातों को हथियार बनाते रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कई अवसरों पर मणिपुर पर अपनी चिंता व्यक्त की। विरोधी दलों के भारी दबाव के कारण भाजपा को अपनी ही सरकार हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा।

अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मणिपुर दौरे से सभी को उचित उत्तर दे दिया है किंतु अब विरोधी दलों को इसमें रुचि नहीं रही क्योंकि उनका मणिपुर नैरेटिव फिलहाल समाप्त होता दिख रहा है। जिस समय भारत में मणिपुर हिंसा पर राजनीति चरम पर थी उस समय यूरोपीय संघ की संसद में मणिपुर को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसे केंद्र सरकार ने भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बताते हुए खारिज कर दिया था अतः मणिपुर को लेकर कांग्रेस ने जो देश विरोधी वैश्विक नैरेटिव चलाया था वह भी अब ध्वस्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुकी बहुल हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित चुराचांदपुर के लिए 7,300 करोड़ रुपए से अधिक और मैतेई बहुल इंफाल के लिए 1,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करके यह संदेश देने का प्रयास किया कि सरकार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत उनके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर यात्रा के दौरान हिंसा पीड़ितों से भेंट करते हुए उन्हें सुरक्षा शांति तथा विकास का भरोसा दिया।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मणिपुर को भारत की मणि बताते हुए कहा कि मणिपुर में उम्मीद और विश्वास की नई सुबह दस्तक दे रही है। किसी

भी स्थान पर विकास के लिए शांति बहुत अनिवार्य है। आपसी संवाद और भरोसे से ही विवाद को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मणिपुर के विभिन्न समुदायों के बीच आपसी संवाद, सम्मान और समझौते को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास रही है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पूर्व गृह मंत्रालय के लगातार प्रयासों के बाद दोनो समुदायों के बीच तनाव कम करने के काफी प्रयास किये है जिनका प्रभाव दिखाई पड़ने लगा है। लगातार चल रहे संवाद के कारण ही कुकी बहुल क्षेत्र से होकर निकलने वाला एनएच दो हाईवे अब पूरी तरह से खुल गया है और जनता व वस्तुओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है। मणिपुर में अभी शांति के लिए कई अहम पड़ाव आने हैं। मैतेयी ओर कुकी समुदाय के बीच कुछ मतभेद अभी भी बरकरार हैं जिनको सुलझाने के प्रयास जारी हैं। इसमें कुकी समुदाय के लोग मणिपुर की छत के नीचे ही अपने लिए एक अलग व्यवस्था की मांग कर रहे हैं फिर भी अब मणिपुर की समस्या का उचित समाधान निकलने की आस जग गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद एक रैली को संबोधित किया जिसमें लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी जो मोदी-मोदी के नारे लगा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जनसमुदाय मान चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से मणिपुर में विकास और शांति लाने वाली एक नयी भोर हुई है।

मणिपुर के पहाड़ी और घाटी जिलों के बीच सद्भाव और संवाद को मजबूत करें: मोदी

दो साल पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद मणिपुर की अपनी पहली यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (13 सितंबर, 2025) को राज्य के पहाड़ी और घाटी जिलों के बीच सद्भाव का एक मजबूत पुल बनाने के लिए संवाद को मजबूत करने का आह्वान किया। मई 2023 में शुरू हुआ जातीय संघर्ष इम्फाल घाटी पर प्रभुत्व रखने वाले मीतेई लोगों और आसपास की पहाड़ियों पर प्रभुत्व रखने वाले कुकी-जो लोगों के बीच है। श्री मोदी ने कहा, 'मुझे खुशी है कि हाल ही में पहाड़ों और घाटियों में विभिन्न समूहों के साथ समझौते पर पहुँचने के लिए बातचीत शुरू हुई है। ये प्रयास संवाद, सम्मान और आपसी समझ के माध्यम से शांति स्थापित करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं। मैं सभी संगठनों से शांति के मार्ग पर आगे बढ़ने, अपने सपनों को साकार करने और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का आग्रह करता हूँ।' उन्होंने कहा कि सरकार विस्थापित परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाने में सहायता प्रदान कर रही है। हाल ही में, राज्य के लिए लगभग ₹3,000 करोड़ का विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है, जबकि विस्थापित लोगों की सहायता के लिए ₹500 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। आदिवासी युवाओं को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि वह 'उनके सपनों और संघर्षों से अच्छी तरह वाकिफ हैं', और वादा किया कि उनकी चिंताओं के समाधान के लिए विभिन्न समाधान निकाले जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, ₹सरकार स्थानीय शासन निकायों को मजबूत करने और उनके विकास के लिए धन का उचित आवंटन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।' इम्फाल में, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और शिविरों में रहने को मजबूर लोगों को अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौटने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार मणिपुर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है।' श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में मणिपुर को पुरानी कठिनाइयों से उबरने में मदद की है। अपनी सरकार द्वारा जीएसटी में उल्लेखनीय कमी का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे मणिपुर के लोगों को दोहरा लाभ होगा। उन्होंने बताया कि कई दैनिक उपयोग की वस्तुएँ – साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, कपड़े और जूते – अब ज्यादा सस्ती हो जाएँगी, साथ ही सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री की कीमतें भी कम हो जाएँगी। उन्होंने कहा कि होटलों और खाद्य सेवाओं पर जीएसटी में उल्लेखनीय कमी से गेस्ट हाउस मालिकों, टैक्सी संचालकों और सड़क किनारे भोजनालयों को भी लाभ होगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

महंगाई से राहत बजट में बचत

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के आठ वर्ष बाद, 2025 को जीएसटी में सुधारों के लिए निर्णायक साल माना जा रहा है। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा की और 22 सितंबर से इसे लागू भी किया जा रहा है। बजट 2025 में सरकार ने कानूनी स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

जीएसटी 2.0: विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था

जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ मंदी की गिरफ्त में हैं, भारत 7.8% की विकास दर से सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। यह केवल कर सुधार नहीं, बल्कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

भारत की आजादी के 75 वर्ष बाद, जब हम 'विकसित भारत' की राह पर बढ़ रहे हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार एक ऐतिहासिक पड़ाव हैं। 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक ने जिस कर ढांचे की घोषणा की, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को सरल, पारदर्शी और जनोन्मुख बनाने का रास्ता खोला है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से

ललित कुमार

जीडीपी में 1-1.2% की अतिरिक्त वृद्धि और मुद्रास्फीति में 1% से अधिक की कमी होगी। इससे भारतीय सामान वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। बीजेपी सरकार ने जहाँ आम नागरिकों और उद्योग जगत को राहत दी है, वहीं विपक्ष पर यह निशाना भी साधा है कि यूपीए सरकार ने आटा, चावल और चाय पर कर लगाया था, जबकि अब एनडीए के तहत ये कर-मुक्त हैं।

2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक यह सबसे बड़ा और व्यापक कर सुधार है। आवश्यक वस्तुओं पर 5%, सामान्य वस्तुओं और सेवाओं पर 18% तथा केवल लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% कर लगाने का

निर्णय न केवल कर ढांचे को सरल करता है, बल्कि इसे जनोन्मुख भी बनाता है।

दैनिक जीवन की जरूरतों - दूध, चावल, आटा, चाय, दही, किताबें और भारतीय रोटी - को या तो शून्य कर या न्यूनतम कर दायरे में लाना गरीब और मध्यम वर्ग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश साफ है कि कोई भी भारतीय परिवार अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए बोझिल न हो। यही 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का वास्तविक रूप है।

स्वास्थ्य सेवाओं को कर-मुक्त करना और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को शून्य करना, आम आदमी की पीड़ा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दशार्ता है। यह कदम न केवल आर्थिक राहत देता है, बल्कि नागरिकों को संकट की घड़ी में गरिमा भी प्रदान करता है। भारत की रीढ़ - किसान - को केंद्र में रखते हुए ट्रैक्टर, सिंचाई प्रणाली, उर्वरक और कीटनाशकों पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे खेती की लागत घटेगी और ग्रामीण समृद्धि को नई दिशा मिलेगी। गृहिणियों और परिवारों को भी राहत मिली है। साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, साइकिल, रेफ्रिजरेटर, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू सामान सस्ते होने से घर-घर में आराम और सुविधा बढ़ेगी। युवाओं की आकांक्षाओं का भी सम्मान किया गया है। छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी में कटौती उन्हें पहली बार खरीदारों के लिए किफायती बनाती है। इससे रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास की राह खुलती है।

बुनियादी ढांचा निर्माण, जो मोदी सरकार की प्राथमिकता है, को सीमेंट पर कर 28% से घटाकर 18% कर देने से नई गति मिलेगी। इससे घरों की लागत कम होगी और बड़े प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे होंगे। एमएसएमई, जो भारत में रोजगार की सबसे बड़ी रीढ़ है, को सरलीकृत अनुपालन और तेज रिफंड से बल मिला है। लंबे समय तक उपेक्षित इस वर्ग को अब नवाचार और विस्तार की नई संभावनाएं मिल रही हैं। स्पष्ट है कि यह सुधार केवल कर ढांचे का बदलाव नहीं है। यह उस'नए भारत' की नींव है, जहां हर वर्ग - गरीब, किसान, महिला, युवा और उद्यमी - राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार है। सरकार की इस पहल से मध्यम वर्ग को भी मजबूती मिलेगी। कांग्रेस, जिसने उन्हें

केवल टैक्स वसूली का साधन बना रखा था, उसके विपरीत भाजपा नीत एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्हें ऐतिहासिक राहत दी है। अब जहाँ आवश्यक वस्तुएँ पूरी तरह कर-मुक्त हैं, वहीं आकांक्षी वस्तुएँ भी सस्ती हुई हैं। इसका सीधा असर कारोबार के विस्तार और खपत में बढ़ोतरी के रूप में दिखेगा।

साथ ही, जीएसटी के सरलीकरण से भारत की लॉजिस्टिक लागत कम हुई है, जिससे भारतीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बने हैं। भाजपा के इन जीएसटी सुधारों ने एक बार फिर भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में उसकी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है।

एक अहम कदम यह है कि दिसंबर 2025 तक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (ऋळअळ) की स्थापना की जाएगी। इससे लंबे समय से व्यवसाय जगत जिन जटिलताओं और देरी से जूझ रहा था, उसका समाधान मिलेगा। यह न्याय, पारदर्शिता और त्वरित निपटारे की दिशा में बड़ा कदम है।

महिला उद्यमियों के संदर्भ में भी ये सुधार दूरगामी महत्व रखते हैं। सरल जीएसटी ढांचा और आसान क्रेडिट पहुँच महिला-नेतृत्व वाले एमएसएमई को विस्तार, नवाचार और रोजगार सृजन के नए अवसर देगा। यह प्रधानमंत्री मोदी की सोच 'नारी शक्ति भारत की प्रगति की चालक है' का ही मूर्त रूप है।

जहाँ तक इन सामूहिक सुधारों के व्यापक आर्थिक प्रभाव की बात है, विशेषज्ञों का अनुमान है कि नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधारों से भारत की जीडीपी में 1 से 1.2 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि और महंगाई में 1 प्रतिशत से अधिक की कमी आएगी। यह भाजपा सरकार के विकास और स्थिरता के संतुलित दृष्टिकोण का प्रमाण है। दुनिया जहाँ मंदी से जूझ रही है, वहीं भारत 7.8 प्रतिशत की दर से सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है-यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की दूरदर्शी और निर्णायक शासनशैली का सशक्त उदाहरण है।

कुल मिलाकर, यह सुधार केवल कर ढांचे का बदलाव नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार के राष्ट्र-निर्माण दृष्टिकोण का हिस्सा है। इन कदमों से भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के संकल्प को नई गति मिली है। जीएसटी सुधार नरेंद्र मोदी सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं जिसमें 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' सिर्फ नारा नहीं, बल्कि ठोस कार्ययोजना है। यह सुधार भारत की आर्थिक संरचना को अधिक न्यायसंगत, प्रतिस्पर्धी और नागरिक-केंद्रित बनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलते हैं।

मोदी सरकार का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक लाभ तक नहीं है बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन

जीएसटी की दरों में हालिया बदलाव ने छोटे उद्योगों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। 2025 में कई सामानों पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं। मिसाल के तौर पर, 28 प्रतिशत के स्लैब से कई उत्पादों को 18 प्रतिशत और कुछ को 12 से 5 प्रतिशत तक लाया गया है।

कोई भी देश तभी आत्मनिर्भर बन सकता है, जब वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खुद बनाए। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना इस दिशा में सबसे जरूरी कदम है। यही वजह है कि दुनिया भर के देश अपने छोटे और कुटीर उद्योगों को मजबूत करने पर जोर देते हैं। देश की समृद्धि तभी संभव है, जब आयात और निर्यात का संतुलन बना रहे और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो। आज वैश्विक दबावों के बीच भारत में स्वदेशी को बढ़ाने की बात जोर-शोर से हो रही है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है जीएसटी

मनोज शर्मा

की दरों में कटौती। उनका लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और जीएसटी में राहत छोटे उद्योगों को सस्ता कच्चा माल और कम लागत देकर इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है। मोदी सरकार का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन भी है। जब देशवासी स्थानीय उत्पादों को अपनाते हैं, तो वे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि अपने इतिहास, कारीगरी और परंपराओं को भी संजोते हैं। आज, भारतीय उपभोक्ता पहले से अधिक सजग हैं। वे समझते हैं कि हर स्वदेशी खरीदारी एक रोजगार का सृजन करती है और एक आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करती है।

घरेलू उद्योगों को एक पहचान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी भारत का

सपना अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों के बाद अब सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में दी जा रही राहतों के जरिए घरेलू उद्योगों को एक नई उड़ान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कुछ आवश्यक घरेलू उत्पादों पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की गई है। इसका सीधा लाभ छोटे और मध्यम दर्जे के स्वदेशी निमाताओं को मिलेगा। इससे न केवल उनकी उत्पादन लागत घटेगी, बल्कि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, हैंडलूम वस्त्र, बांस उत्पाद, घरेलू खिलौने और आयुर्वेदिक दवाओं पर जीएसटी दरों में राहत दी गई है, जो ग्रामीण भारत और पारंपरिक उद्योगों को एक नई ऊर्जा देगी।

छोटे कारोबारियों को फायदा

जीएसटी की दरों में हालिया बदलाव ने छोटे उद्योगों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। 2025 में कई सामानों पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं। मिसाल के तौर पर, 28 प्रतिशत के स्लैब से कई उत्पादों को 18 प्रतिशत और कुछ को 12 से 5 प्रतिशत तक लाया गया है। इससे उत्पादन की लागत कम होगी, खासकर हैंडीक्राफ्ट्स और लेदर-फुटवेयर जैसे क्षेत्रों में, जहां जीएसटी 12 से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि छोटे कारोबारियों को कच्चा माल सस्ता मिलेगा, उनकी लागत 7-8 प्रतिशत तक कम होगी, और वे बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इस कदम से न सिर्फ उत्पादन सस्ता होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी और अन्य सामानों पर जीएसटी 28 से 18 प्रतिशत होने से उनकी कीमतें 7-8 प्रतिशत तक कम हो सकती हैं। इससे लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, खासकर ऑटो, कंज्यूमर गुड्स और एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में। नतीजतन, छोटे उद्योगों की के सामान की बिक्री बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वैश्विक बाजार में और प्रतिस्पर्धी बनेंगी

जीएसटी में कटौती का एक और बड़ा फायदा निर्यात के क्षेत्र में दिखेगा। कम टैक्स से भारतीय उत्पादों की कीमतें वैश्विक बाजार में और प्रतिस्पर्धी बनेंगी। खासकर लेदर और फुटवेयर जैसे निर्यात-आधारित उद्योगों को इससे खासा लाभ होगा। ये क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, और इनकी मजबूती से ग्रामीण और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट्स जैसे क्षेत्रों में कारीगरों को सस्ता कच्चा माल और बेहतर मुनाफा मिलेगा, जिससे उनकी आजीविका सुधरेगी।

वोकल फॉर लोकल का नारा

भारत विविधताओं वाला देश है, जहां हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं, कारीगरी, उत्पाद और संस्कृति है, लेकिन वैश्वीकरण के कारण हमारे देश के लोकल उत्पादों की उपेक्षा होती रही है। इस स्थिति को बदलने के लिए भारत सरकार ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो आत्मनिर्भर भारत की नींव रखता है वोकल फॉर लोकल का अर्थ है स्थानीय उत्पादों के लिए आवाज उठाना और उनका समर्थन करना। इसका उद्देश्य है कि हम देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता दें, उन्हें अपनाएं, और उनके प्रचार-प्रसार में मदद करें ताकि स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को प्रोत्साहन मिले।

आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम

विदेशी उत्पादों पर निर्भरता को कम कर स्वदेशी उत्पादों को अपनाना भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। जब हम स्थानीय उत्पादों को खरीदते हैं, तो इससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। हमारे देश की हस्तकला, कपड़ा उद्योग, मिट्टी के बर्तन, और अन्य पारंपरिक उत्पादों को समर्थन मिलता है। देश में ही उत्पादन और खपत से पैसे का प्रवाह देश के भीतर रहता है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

आम जनता की भूमिका रहे

हमें विदेशी ब्रांड्स के पीछे भागने की बजाय भारतीय उत्पादों को अपनाना चाहिए। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोकल उत्पादों का प्रचार करना चाहिए। त्योहारों और अन्य अवसरों पर भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए सामान का उपयोग करें। उदाहरण के तौर पर आज खादी, हैंडलूम, हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक उत्पाद जैसे पतंजलि आदि को अपनाकर लोग वोकल फॉर लोकल को समर्थन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चिकनकारी, कश्मीर का कढ़ाईदार वस्त्र, और राजस्थान की हस्तशिल्प कलाएं सब हमारी लोकल ताकतें हैं।

गेम-चेंजर साबित होगा फैसला

कुल मिलाकर, जीएसटी सुधार छोटे उद्योगों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। यह न केवल उनकी दक्षता बढ़ाएगा, बल्कि टैक्स की जटिलता को भी कम करेगा। हालांकि इससे सरकारी राजस्व में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन लंबे समय में यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और विकास दर को बढ़ावा देगा। मोदी जी का यह कदम स्वदेशी को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह छोटे उद्योगों को नई उड़ान देने का वादा करता है, जिससे न सिर्फ कारोबारी, बल्कि पूरा देश समृद्ध होगा।

पुलिस हिरासत में मौतें पुलिस तंत्र की भयावह तस्वीर है

सचिन तोमर

राजस्थान में लगातार हो रही हिरासत में मौतों ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन मामलों में पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न कराना संदेह पैदा करता है। अदालत ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

बिहार के वैशाली में पुलिस कस्टडी में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस हिरासत में कथित मौत की यह घटना सुप्रीम कोर्ट के करीब एक सप्ताह पहले राजस्थान में ऐसी मौतों पर राज्य सरकार से जवाब तलब के बाद हुई है। यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौतों को लेकर जवाब तलब किया है। इससे पहले भी ऐसी मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट गाइड लाइन जारी कर चुका है। इसके बावजूद देश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पुलिस हिरासत में मौतों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। देशभर के थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने हिरासत में मौत को लेकर रिपोर्ट पर कहा कि 2025 में पिछले 7-8 महीनों में अकेले राजस्थान में ही पुलिस हिरासत में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि, 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुना चुका है। इसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जाने के निर्देश दिए गए थे। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस सीसीटीवी फुटेज देने से बचती है। इसके पीछे पुलिस की तरफ से कई तरह के कारण बताए जाते हैं, जैसे कि तकनीकी खराबी, फुटेज स्टोरेज की कमी, जांच जारी है या कानूनी प्रतिबंध।

कई मामलों में तो पुलिस ने फुटेज देने से सीधे इनकार कर दिया या जानबूझकर देरी की। अदालत ने साफ कहा था कि थाने का कोई भी हिस्सा निगरानी से बाहर नहीं होना चाहिए। लॉकअप से लेकर मेन गेट, कॉरिडोर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के कमरे, ड्यूटी रूम और थाने का पूरा कैंपस सीसीटीवी कवरेज में होना चाहिए। साथ ही, सीबीआई, ईडी, एनआईए, एनसीबी और डीआरआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के दफ्तरों में भी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए थे। इनका

डेटा कम से कम एक साल तक सुरक्षित रहे। इन मामलों से यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के इन निदेर्शों का पालन पूरी तरह से नहीं किया गया है। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की समीक्षा के लिए बनाई गई केंद्रीय और राज्य स्तरीय कमेटियां भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं।

राजस्थान में लगातार हो रही हिरासत में मौतों ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन मामलों में पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न कराना संदेह पैदा करता है। अदालत ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि राजस्थान में बीते दो साल में पुलिस हिरासत में 20 लोगों की मौतें हुई। लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी को मौत का दोषी नहीं माना गया। इनमें पांच व्यक्तियों की मौत हार्ट अटैक से होना बताया गया जबकि एक व्यक्ति ने कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया था। दो मामलों में संतरियों को 17 सीसी के नोटिस थमाए गए हैं। शेष 14 मामलों में अभी तक मौत का कोई कारण सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि इन मामलों की जांच करवाई जा रही है। पुलिस हिरासत में मौतों की खबर भारत में जैसे बहुत आम है। लगभग रोज अखबारों में जेल में या पुलिस की हिरासत में मारे जाने वालों की खबर छपती है। 26 जुलाई 2022 को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि 2020 से 2022 के बीच 4484 लोगों की मौत हिरासत में हुई थी। मानवाधिकार आयोग ने माना कि 2021-22 में जेलों में 2152 लोग मारे गए। इनमें 155 मौतें पुलिस हिरासत में हुई थीं। लेकिन सवाल है, देश में हिरासत में इतनी मौतें क्यों होती हैं? क्या पुलिस व्यवस्था हिरासत में या जेल काट रहे कैदियों के साथ अमानवीय बरताव करती है? क्या वह कानूनों का खयाल नहीं रखती? कॉमन कॉज के एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर पुलिसवाले टॉर्चर और हिंसा को अपने काम के लिए जरूरी मानते हैं। 30 फीसदी पुलिसवाले गंभीर मामलों में थर्ड डिग्री टॉर्चर को सही मानते हैं। जबकि 9 फीसदी यहां तक मानते हैं कि छोटे-मोटे अपराधों में भी ये सही है।

प्रकाश कदम बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी मुठभेड़ों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। न्यायालय ने कहा कि जिन मामलों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ फर्जी मुठभेड़ साबित होती है, उन्हें दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम मानते हुए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी गई कि उन्हें मुठभेड़ के नाम पर हत्या करने के लिए इस बहाने से माफ नहीं किया जाएगा कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों या राजनेताओं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों के आदेशों का पालन कर रहे हों। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यातना को संविधान या अन्य दंडात्मक कानूनों में परिभाषित नहीं किया गया है। किसी मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को दी जाने वाली यातना, मूलतः कमजोर पर शक्तिशाली की इच्छा को पीड़ा देकर थोपने का एक साधन है।

आज यातना शब्द मानव सभ्यता के अंधकारमय पक्ष का पर्याय बन गया है। यातना और अन्य क्रूर अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले 170 देशों में से, भारत उन आठ देशों में से एक है जिन्होंने अभी तक इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन नहीं किया है। अपने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, विधेयक में कहा गया है कि इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन भारत सरकार की बुनियादी सार्वभौमिक मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। विधि आयोग की 273वीं रिपोर्ट में कहा गया कि हिरासत में मौतें सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं हैं, बल्कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में गहरी अस्वस्थता का लक्षण हैं। संवैधानिक गारंटी, कानूनी सुरक्षा उपायों और न्यायिक घोषणाओं के बावजूद, हिरासत में यातना और दुर्व्यवहार का प्रयोग व्यापक रूप से जारी है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जहाँ किसी लोक सेवक को हिरासत में यातना देना साबित हो जाता है, वहाँ यह साबित करने का भार कि यातना जानबूझकर नहीं दी गई थी, या लोक सेवक की सहमति या सहमति से नहीं दी गई थी, लोक सेवक पर आ जाएगा। आयोग के मसौदे में हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान था। मसौदे में पीड़ित को मुआवजा देने का भी प्रावधान था। यह रिपोर्ट धूल चाट रही है। राजनीतिक दलों को ऐसे मामलों में तभी चिंता होती है, जब वे विपक्ष में होते हैं। सत्ता मे आते ही नेता गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में पुलिस कानूनों में सुधार किया है, किन्तु हिरासत में मौतें और प्रताड़ना जैसे मामलों में जिम्मेदारी तय नहीं की गई और न ही किसी तरह के मुआवजे का प्रावधान किया गया। पुलिस के खिलाफ ऐसे मामलों में जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक हिरासत में मौतों से देश शर्मसार होता रहेगा।

आरक्षण में क्रीमी लेयर पर राजनीतिक दलों की चुप्पी

देश में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, जिसे हर राजनीतिक दल लपकने को तैयार रहता है। राजनीतिक दलों को लगता है कि बहुआयामी विकास के मुद्दे के बजाए आरक्षण की पैरवी करके सत्ता पाना ज्यादा आसान है। इसके लिए नेता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। यहां तक कि अदालतों के निर्णयों को भी चुनौती देने में पीछे नहीं रहते। नेताओं की दिलचस्पी आरक्षण को बढ़ाने में रहती है। आरक्षण की जरूरत है या नहीं, इस पर चर्चा तक करने से कतराते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की आय सीमा से संबंधित को संसदीय समिति की आठवीं रिपोर्ट में आय सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की है।

समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि आय सीमा को 6.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष करने संबंधी संशोधन 2017 में

एन के शर्मा

किया गया था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के नियमों के अनुसार, इस सीमा की समीक्षा हर तीन साल पर या जरूरत पड़ने पर उससे पहले भी की जानी चाहिए। भाजपा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने कहा कि वर्तमान सीमा कम है, जिसके दायरे में ओबीसी का केवल एक छोटा सा हिस्सा आता है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति और निम्न आय वर्ग की बढ़ती आय के कारण इसमें वृद्धि करना समय की मांग है। संभव है कि संसद में इस समिति की सिफारिश मानते हुए आय सीमा बढ़ा दी जाए। इस पर शायद ही कोई राजनीतिक दल ऐतराज करे। राजनीतिक दलों में इतना साहस ही नहीं है कि आरक्षण की सीमा तय करने और उसके प्रभावों पर किसी तरह की चर्चा करें। इसके विपरीत आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा रहती है। यही वजह है कि जब-जब आरक्षण में क्रीमी की पहचान कर अलग करने की बात की जाती है, तब राजनीतिक दलों को काठ मार जाता है। क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा से सभी राजनीतिक दल भयभीत रहते हैं कि कहीं उनका वोट खिसक नहीं जाए। आरक्षित वर्ग के हित में होने के बावजूद कोई भी राजनीतिक दल क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर करना तो दूर, बल्कि इस पर सार्वजनिक तौर पर बहस तक करने को तैयार नहीं है। जबकि यदि क्रीमी

लेयर की पहचान कर उसे आरक्षण से बाहर कर दिया जाए तो आरक्षण से वंचित उसी वर्ग के लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा।

संसदीय समिति की जो रिपोर्ट संसद में रखी गई है, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की आय सीमा बढ़ाने की सिफारिश तो गई है किन्तु क्रीमी लेयर का जिक्र तक नहीं किया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पुनर्विचार निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें राज्यों को आरक्षण के संबंध में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) जैसे आरक्षित श्रेणी समूहों को उप-वगीर्कृत करने का अधिकार दिया गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि एसटी-एसटी क्रीमीलेयर को लेकर रिजर्वेशन में कैटेगरी बनाई जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय में कहा गया कि क्रीमी लेयर सिद्धांत, जो पहले केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर लागू होता था (जैसा कि इंद्रा साहनी मामले में उजागर किया गया था) अब एससी और एसटी पर भी लागू होना चाहिए। इसका मतलब है कि राज्यों को एससी और एसटी के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। उसे आरक्षण के लाभ से बाहर करना चाहिए। अदालत ने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। यदि परिवार में किसी पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ ले लिया है और उच्च दर्जा प्राप्त कर लिया है, तो आरक्षण का लाभ तार्किक रूप से दूसरी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होगा। इस निर्णय में विभिन्न राज्यों के कानूनों को बरकरार रखा गया, जिन्हें पहले रद्द कर दिया गया था, जैसे कि पंजाब और तमिलनाडु के कानून, जो राज्यों को एससी और एसटी समूहों के भीतर उप-श्रेणियां बनाने की अनुमति देते हैं।

अर्थात राज्य मौजूदा आरक्षण के दायरे में ही अति पिछड़ों की पहचान कर उसे अलग से आरक्षण दे सकते हैं। इस पर भी ज्यादातर राज्य खामोश हैं। उन्हें लगता है इससे जिस वर्ग का आरक्षण कम हुआ है, वह नाराज नहीं हो जाएगा और वोट नहीं देगा। ऐसा करने से कहीं उस वर्ग का वोट बैंक हाथ से नहीं खिसक जाए, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एक साल होने के बाद भी ज्यादातर राज्यों ने आरक्षित दायरे में अति पिछड़ों की पहचान कर उन्हें अलग से आरक्षण देने की कवायद तक नहीं की।

क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर देश के किसी भी राजनीतिक दल और सरकारों ने चर्चा तक नहीं की। जबकि कोर्ट का साफ कहना था कि क्रीमी लेयर को हटाने से उसी वर्ग के वंचित लोगों को आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। राजनीतिक दलों ने पहले कभी ओबीसी के क्रीमी लेयर का जिक्र तक नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एससी-एसटी को भी शामिल कर लिया। यह मुद्दा नेताओं के लिए अत्यधिक ज्वलनशील हो गया। क्रीमी लेयर को हटाना तो दूर रहा कोई इसके दायरे पर बहस तक करने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत राजनीतिक दल आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को हटाने पर तत्पर हैं।

नेताओं को लगता है कि आरक्षण की सीमा में नए वर्गों को शामिल करने से उनका वोट बैंक मजबूत होगा। यह अलग बात है कि आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को हटाने के उनके मंसूबों को सुप्रीम कोर्ट ने सफल नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को यह घोषणा की थी कि आगामी जनगणना के साथ-साथ जाति गणना भी की जाएगी। इसके तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में कोटा पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने की अपनी मांग दोहराई। राहुल गांधी ने कहा, ‘रिजर्वेशन पर 50 प्रतिशत की सीमा हमारे देश की प्रगति और पिछड़ी जातियों, दलितों और आदिवासियों की प्रगति में बाधा बन रही है और हम चाहते हैं कि इस बाधा को समाप्त किया जाए।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 50 प्रतिशत कोटा सीमा का हवाला देते हुए आरक्षण के प्रयासों को खारिज कर चुका है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की पैरवी करने वाले राहुल गांधी ने एक बार भी क्रीमी लेयर को हटाने की बात नहीं कही। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को लगता है कि आरक्षण का दायरा बढ़ा कर वोट बैंक बढ़ाना ज्यादा आसान है। इसके विपरीत देश में विकास, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चुनाव जीतना आसान नहीं हैं। यही वजह है राजनीतिक दल आरक्षण का कई पीढियों से लगातार फायदा ले चुके वर्ग को भी आरक्षण के दायरे से बाहर करने से कतराते रहे हैं। बेशक इससे दूसरे आरक्षित वर्ग का हिस्सा हड़पा जाता रहे।

अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण मंदिर से संबंधित उत्पादों की बिक्री से केवल जनवरी माह में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो सकता है, वहीं अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति भारत के प्राय सभी हिंदू घरों में अनिवार्य रूप से स्थापित होगी तथा सदियों से मोहब्बत की निशानी ताजमहल को रिप्लेस कर देगी।

पानी की बूंद कीमती: जल संरक्षण के लिए जन-आंदोलन की जरूरत

अरुण शर्मा

जल संकट की गंभीरता और पानी की एक-एक बूंद के महत्व को समझाते हुए 'पानी की पाठशाला' के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में राष्ट्रीय अभियान को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। जल शक्ति विद्यापीठ के प्रयास से देशभर में लगभग 5000 पानी की पाठशालाओं की स्थापना की गई है, जिनमें बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर के साथ-साथ मुजफ्फरनगर, शामली, झांसी, कानपुर नगर, घाटमपुर जैसे जिलों को भी शामिल किया गया है। यह पहल न केवल जल संरक्षण के महत्व को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम है, बल्कि आगामी वैश्विक जल संकट का सामना करने के लिए हम सबको जागरूक करने का एक सशक्त अभियान भी है। भारत सरकार भी भारत में जल संकट ना हो उसके लिए कई योजना चल रही है जिसमें कई योजनाएं शामिल हैं:

जल जीवन मिशन 2025

इस योजना के तहत अभी तक देश के 80% ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की पहुंच हो चुकी है। यह मिशन 2028 तक हर गांव में 100% नल कनेक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों ने इस योजना को बड़े पैमाने पर सफल बनाया है। इससे लाखों ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिली है, जो जल संरक्षण और स्वस्थ जीवन के लिए बेहद आवश्यक है।

जल पखवाड़ा (16-30 अप्रैल)

सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल अप्रैल में जल पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसमें स्कूलों और स्थानीय संस्थाओं में जल संरक्षण की जागरूकता हेतु विशेष कार्यक्रम, कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। यह बच्चों और युवाओं में जल संरक्षण के महत्व को समझाने और उन्हें सक्रिय भागीदार बनाने का प्रभावी माध्यम है।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन

2025 में हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से जल संरक्षण को तेज करने के लिए यह अभियान चला रहा है। इसका फोकस वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और सामुदायिक भागीदारी पर है। 'हर बूंद अनमोल' का यह संदेश राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण को प्राथमिकता देता है।

जल संकट की भयावह स्थिति:

ग्लेशियरों के पिघलने और अत्यधिक जल उपयोग के कारण जल उपलब्धता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। 2025 तक विश्व की 14% आबादी जल संकट की स्थिति का सामना कर सकती है। इसलिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जल संरक्षण के घरेलू और सामुदायिक उपाय:

पानी की पाठशाला में नलों की लीकेज रोकना, कम पानी का उपयोग, वर्षा जल संचयन, तालाबों व कुओं का पुनरुद्धार, जल प्रदूषण रोकने के लिए स्वच्छता अभियान जैसे विषय विशेष रूप से सिखाए और प्रोत्साहित किए जाते हैं।

विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि यदि जल संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में जल युद्ध संभव हैं। इसलिए इसे रोकने के लिए अब से ही सामाजिक, शैक्षिक और सरकारी स्तर पर ठोस कदम जरूरी हैं।

सरकारी नीतियां और समुदाय की भागीदारी:

जल शक्ति विद्यापीठ तथा पद्मश्री उमा पांडे के नेतृत्व में जल संरक्षण के लिए नए संगठनात्मक एवं तकनीकी प्रयास हो रहे हैं, जिनमें सूचना, शिक्षा एवं संचार (कएउ) गतिविधियां अहम भूमिका निभा रही हैं। स्थानीय समुदाय, स्कूल, पंचायतें और स्वयंसेवी संस्थाएं

इस अभियान का हिस्सा बन रही हैं।

जल शक्ति विद्यापीठ और पद्मश्री उमा पांडे के सहयोग से चल रहे इस अभियान को जल शक्ति विद्यापीठ के सचिव डॉ. अंकित पांडेय ने प्रारंभ किया है, जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन तीव्र गति से पूरे देश में फैल रहा है। पानी की पाठशाला के तहत लोगों को जल संरक्षण के वैज्ञानिक तरीके, जल स्त्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल प्रदूषण नियंत्रण, तथा जल के उपयोग में दक्षता बढ़ाने के गुर सिखाए जाते हैं। पानी की पाठशाला न केवल जल संरक्षण का एक अनुपम शिक्षा माध्यम हैं, बल्कि ये पूरे देश में जल सुरक्षा का आधार भी बन रही हैं। यदि हर नागरिक जल की हर बूंद की कीमत समझे और संरक्षण के लिए सक्रिय हो, तो हम भविष्य में जल संकट से सुरक्षित रह सकते हैं। जल शक्ति विद्यापीठ का यह मिशन ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब जल संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं और जल संरक्षण के बिना किसी स्थायी विकास की कल्पना असंभव है।

पानी एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसे न तो बनाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है, इसलिए हमें इसे बचाने और संरक्षित करने की अति आवश्यक तत्परता दिखानी होगी। जलीय संसाधनों के संरक्षण व उचित उपयोग से न केवल आज के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। यदि इस दिशा में हम व्यापक स्तर पर प्रयास नहीं करते हैं, तो जल संकट भविष्य में युद्धों और संघर्षों का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगला विश्व युद्ध जल के लिए ही हो सकता है। ऐसे में पानी की पाठशालाओं का उद्देश्य समुदायों को जल संरक्षण की शिक्षा देना, जागरूकता फैलाना और व्यवहारिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है।

देश में जल संकट के मुख्य कारणों में अत्यधिक जल उपयोग, जल प्रदूषण, बेवजह का अपव्यय, और जल स्त्रोतों का दोहन शामिल हैं। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र जहां पानी की कमी अधिक रहती है, वहाँ इस पहल की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पानी की पाठशालाओं में स्थानीय जनता को जल संकट का यथार्थ समझाया जाता है, जिससे वे स्वयं जल संरक्षण के लिए कदम उठा सकें। इस अभियान के अंतर्गत वर्षा जल संचयन पर बल दिया जाता है। वर्षा के जल को जमा कर उसे उपयोग में लाने की विधि और तकनीकें। जल संरक्षण के घरेलू उपाय भी हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जल बचाने के सरल उपाय, जैसे नलों की लीकेज रोकना, कम पानी में काम करना आदि।

जल स्त्रोतों में प्रदूषित पदार्थों के गिरने से रोकना और स्वच्छ जल की उपलब्धता बनाये रखना।स्थानीय समुदायों को जल प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण जैसे तालाब, नदी, कुंए आदि के संरक्षण के महत्व को समझाना। इसके साथ ही जल सुरक्षा से जुड़े सरकारी कानूनों और अधिकारों की जानकारी देना। इसके साथ ही, पानी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए और जल संकट के बढ़ते प्रभावों को समझकर यह भी आवश्यक है कि सरकारें, संस्थाएं और आम जनता मिलकर जल संरक्षण के लिए ठोस नीतियां और प्रयास करें। जल शक्ति विद्यापीठ जैसी संस्थाओं का यह अभियान एक प्रेरणादायक मिसाल है, जो हमें जल संरक्षण के लिए एकजुट करता है।

पानी की पाठशालाएं ना केवल शिक्षा का माध्यम हैं, बल्कि यह परिवर्तन लाने वाली सामूहिक शक्ति भी हैं। यदि हम सब मिलकर पानी बचाने के लिए हर स्तर पर योगदान दें, तो हम आने वाले जल संकट की विभीषिका से बच सकते हैं। जल संकट का समाधान तभी संभव है जब हर व्यक्ति, परिवार और समुदाय पानी की बचत के प्रति सचेत और सक्रिय हो।

पेट्रोल पंप की तरह भविष्य में वाटर पंप की व्यापक उपलब्धता की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जल संकट के प्रति सचेत नागरिकों की संख्या बढ़नी चाहिए, ताकि जल की हर बूंद की कीमत समझी जाए। जल शक्ति विद्यापीठ का यह मिशन जल संरक्षण को जन-जन तक पहुंचाने का एक बेहतरीन प्रयास है, जिसका समर्थन हम सभी को करना चाहिए, ताकि जल संकट को खत्म कर सकें और जल की महिमा को संरक्षित रख सकें।

विकराल होते आनलाइन गेम पर नियंत्रण का कानून सराहनीय

ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी लत रिश्तों को तोड़ रही है, दोस्ती और पारिवारिक बंधनों को कमजोर कर रही है। एक पूरी पीढ़ी, जिसे राष्ट्रनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता इस आभासी जुए में गँवा रही है।

इंटरनेट के विस्तार ने आधुनिक दौर में जीवन को अनेक सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ नए गंभीर संकट भी पैदा किए हैं। इनमें सबसे गंभीर संकटों में से एक है ऑनलाइन गेमिंग या कहें तो मनी गेमिंग की बढ़ती लत। यह सच है कि गेमिंग मनोरंजन का साधन हो सकता है, पर जब इसमें धन का जुड़ाव होता है, तब यह सीधा-सीधा जुए एवं सट्टे के रूप में बदल जाता है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग यदि लत बन जाए तो यह संपन्न व्यक्ति एवं परिवार को भी कंगाल कर सकता है। एक आंकड़े के अनुसार देश में एक साल में 45 करोड़ लोगों ने बीस हजार करोड़ गवां दिये हैं। सब कुछ गंवा कर आत्महत्या करने के मामले भी प्रकाश में आते रहे हैं। सवाल इन लालच बेचने एवं जगाने वाली मनी

मुहम्मद परवेज अख्तर
संतकबीरनगर

गेमिंग की पारदर्शिता को लेकर भी उठते रहे हैं। इन्हीं चिंताओं एवं त्रासद विडम्बनाओं के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण का एक विधेयक भारत सरकार इसी मानसून सत्र में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 लेकर आई है। जिसे अब गंभीर चर्चा के बिना संसद ने पारित भी कर दिया है। यह विधेयक पैसे से खेले जाने वाले किसी भी ऑनलाइन गेम को गैरकानूनी घोषित करता है। यह स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि गेमिंग के नाम पर अरबों रुपए का लेन-देन और करोड़ों युवाओं की मानसिक शांति को नष्ट करने वाली प्रवृत्ति दिनोंदिन विकराल रूप ले रही है।

आज स्थिति यह है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत केवल समय और धन की बबार्दी ही नहीं कर रही, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव और विघटन का कारण बन रही है। स्कूल और कॉलेज के छात्र अपनी पढ़ाई की उपेक्षा कर इस आभासी दुनिया में डूबते जा रहे हैं। युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा रात-दिन गेमिंग में डूबा रहता है, जिससे उनके व्यक्तित्व और भविष्य पर गहरा नकारात्मक असर पड़ रहा है। यह संकट केवल आर्थिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक भी है। दिन-रात स्क्रीन से चिपके रहने वाले युवक चिड़चिड़ापन, अवसाद और एकाकीपन का शिकार

हो रहे हैं। उनमें हिंसक प्रवृत्तियां भी उभर रही हैं। कई ऐसी खबरें भी आ चुकी है, जिनमें लगातार आनलाइन गेम खेलते रहने से मना करने पर कोई किशोर हिंसक हो गये और उसने या तो आत्महत्या कर ली या फिर किसी की जान ले ली। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी लत रिश्तों को तोड़ रही है, दोस्ती और पारिवारिक बंधनों को कमजोर कर रही है। एक पूरी पीढ़ी, जिसे राष्ट्रनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता इस आभासी जुए में गँवा रही है। सरकार के मुताबिक, वह ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के लिये अवश्य उत्सुक है, जिसमें कोई वित्तीय जोखिम न हो। यहां उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन गेमिंग का वार्षिक राजस्व 31,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके साथ ही यह हर साल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है। लेकिन इसके साथ चिंता का विषय यह भी है कि सुनहरे सब्जबाग दिखाने वाले कई ऑनलाइन गेमिंग एप लत, खेलने वाले आम लोगों के आर्थिक नुकसान और मनी लॉन्ड्रिंग को भी बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग में अपनी जमा पूंजी लुटाने वाले बदकिस्मत उपयोगकर्ता नाकामी के बाद आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं।

निस्संदेह सरकार ने राजस्व की परवाह न करते हुए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर एक बड़ा जोखिम भी उठाया है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या केवल कानून से इस प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकेगा? इंटरनेट का विस्तृत दायरा और विदेशी ऑनलाइन ऑपरेटर विधेयक के प्रमुख उद्देश्यों को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। यह नितांत अपेक्षित है कि वित्तीय प्रणालियों की अखंडता के साथ-साथ राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए। माना जा रहा है कि इस नये कानून को बनाने की जरूरत संभवतः छह हजार करोड़ रुपये वाले महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले के बाद महसूस की गई। जिसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ शीर्ष राजनेताओं और नौकरशाहों पर सट्टेबाजी एप के यूएई स्थित प्रमोटरों के साथ संबंध होने के आरोप लगे हैं। जो कथित तौर पर हवाला कारोबार और विदेशों में धन-शोधन के कार्यों में लिप्त बताये जाते हैं। भारत सरकार का यह कदम इसलिए भी जरूरी एवं प्रासंगिक है कि इस उद्योग का टर्नओवर कई आर्थिक, राष्ट्रीय एवं सामाजिक विसंगतियों

के साथ कई हजार करोड़ तक पहुंच गया है। विदेशी कंपनियां भी इस क्षेत्र में सक्रिय होकर भारतीय युवाओं को लुभाने के लिए तरह-तरह के विज्ञापन और प्रलोभन दे रही हैं। इन मंचों पर जीतने की लालच में फंसकर युवा अपने उज्ज्वल भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। यह प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं बिगाड़ती, बल्कि राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक है, क्योंकि जिन युवाओं को शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रनिर्माण में योगदान देना चाहिए, वे अपना समय और ऊर्जा इन आभासी खेलों में गवां रहे हैं। आज जरूरत है कि ऑनलाइन गेमिंग की इस समस्या को केवल कानूनी दायरे में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी गंभीरता से लिया जाए। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को समय पर समझाएं, उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करें। समाज को भी मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि मनोरंजन के नाम पर फैल रहे इस जुए की घातक एवं विध्वंसक संस्कृति को बढ़ावा न दिया जाए। यह ठीक है कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग

को नियंत्रित करने का प्रस्ताव पारित कर एक सही दिशा में सराहनीय कदम बढ़ाया है, लेकिन कानून से भी अधिक जरूरी है जागरूकता। जब तक लोग स्वयं यह नहीं समझेंगे कि गेमिंग का यह जुआ उनके भविष्य को तबाह कर रहा है, तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम मनोरंजन के नाम पर छल रही इस प्रवृत्ति का पदार्फाश करें और अपने युवाओं को सुरक्षित, रचनात्मक और सकारात्मक भविष्य की राह पर अग्रसर करें। असंख्य परिवारों को आज अपने बच्चों की इस आदत के कारण कर्ज और बर्बादी में अंधेरों में जाने से बचाये। खेल के नाम पर ऑनलाइन मंचों पर पैसा लगाना दरअसल सट्टेबाजी ही है, जिसमें जीत की संभावना क्षणिक होती है और हार की संभावना लगभग निश्चित। लाखों युवक अपने खून-पसीने की कमाई या माता-पिता की मेहनत की कमाई को इन कंपनियों की तिजोरियों में डाल रहे हैं। यह समस्या अब जुए की लत से भी अधिक खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि इसमें तकनीक की चकाचौंध और आसानी से उपलब्धता ने युवाओं को पहले से ज्यादा असुरक्षित बना दिया है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग का बाजार बीते कुछ वर्षों में तेजी से फैला है।

विज्ञापनों, प्रलोभनों और चमकदार ऑफरों ने युवाओं को अपने शिकंजे में इस तरह जकड़ लिया है कि लाखों लोग इसमें डूबकर अपनी शिक्षा, करियर और परिवार तक को दांव पर लगा बैठे हैं। जब खेल केवल मनोरंजन तक सीमित रहता है तब तक उसकी उपयोगिता है, पर जैसे ही इसमें धन और लालच का तत्त्व जुड़ता है, यह जुए में बदल जाता है। और यही वह बिंदु है जहां से विनाश की शुरूआत होती है। सच्चाई यह है कि ऑनलाइन गेमिंग का जाल इतना व्यापक हो चुका है कि इसे रोकने के लिए कानून की सख्ती के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता और पारिवारिक हस्तक्षेप भी उतने ही जरूरी हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग के सख्त नियमन और इसे भारी कराधान के अधीन लाना एक व्यावहारिक समाधान होगा। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देकर उपभोक्ताओं के लिये सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने की भी जरूरत है। इस अभियान में गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त प्लेटफॉर्मों पर जुमार्ना भी लगाना एवं बड़े-बड़े दावे करने वाली मशहूर हस्तियों पर कार्रवाई भी होते हुए दिखनी चाहिए, तभी यह कानून कारगर एवं प्रभावी बन पायेगा।

माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद की बदलती शैली

मानव समाज का आधार परिवार है और परिवार की आत्मा है संवाद। संवाद ही वह सेतु है जिसके माध्यम से माता-पिता और बच्चों के बीच भावनाएँ, विचार और अनुभव साझा होते हैं। किंतु बदलते समय, तकनीक और जीवनशैली के प्रभाव से इस संवाद की शैली भी निरंतर बदल रही है। परंपरागत परिवारों में संवाद का स्वरूप अलग था और आज के आधुनिक परिवारों में यह बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। एक समय में हमारे परिवारों में परंपरागत संवाद शैली व्याप्त थी। उस समय माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद अधिकतर अनुशासन और संस्कार पर आधारित होता था। बच्चे बड़ों के सामने कम बोलते, उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनका कर्तव्य माना जाता। बातचीत का केंद्र 'आदेश और पालन'पर टिका रहता। बड़ों के अनुभवों को अंतिम सत्य माना जाता था और बच्चे उनसे प्रश्न करने से भी हिचकते थे। कहावत थी

अजीत शर्मा

कि बड़ों की डांट में भी भलाई छिपी होती है। इस तरह संवाद में एकतरफा प्रवाह अधिक दिखता था। वर्तमान समय की परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। शिक्षा का प्रसार, तकनीक की उपलब्धता और वैश्विक दृष्टिकोण ने बच्चों की सोच को स्वतंत्र बनाया है। बच्चे अब केवल आदेश मानने वाले नहीं रह गए हैं बल्कि तर्क प्रस्तुत करने वाले, अपनी राय रखने वाले और निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बन रहे हैं। अब संवाद केवल अनुशासन का विषय न होकर पारस्परिक समझ और सहभागिता पर आधारित हो गया है। इस दौर में तकनीक का प्रभाव अधिक देखा जा रहा है।

> एक समय में हमारे परिवारों में परंपरागत संवाद शैली व्याप्त थी। उस समय माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद अधिकतर अनुशासन और संस्कार पर आधारित होता था। बच्चे बड़ों के सामने कम बोलते, उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनका कर्तव्य माना जाता।

मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने संवाद की प्रकृति को गहराई से प्रभावित किया है। पहले घर के आँगन, चौपाल या भोजन की मेज पर बातचीत होती थी, वहीं अब अधिकांश संवाद 'व्हाट्सएप चैट' या वीडियो कॉल तक सीमित हो गया है। कभी-कभी तो एक ही घर में रहते हुए भी

माता-पिता और बच्चे सीधे न बोलकर संदेशों के माध्यम से बात करते हैं। यह सुविधा होने के साथ-साथ दूरी का भी कारण है। तकनीक ने संवाद को तेज और सुविधाजनक बनाया है परंतु भावनात्मक आत्मीयता में कमी भी आई है।

पीढ़ीगत अंतर के कारण भी संवाद शैली में सबसे बड़ा बदलाव आया है। माता-पिता का पालन-पोषण परंपरागत परिवेश में हुआ, जहाँ अनुशासन सर्वोपरि था जबकि आज के बच्चों की परवरिश आधुनिक और स्वतंत्र सोच वाले वातावरण में हो रही है। इसलिए दोनों पीढ़ियों की अपेक्षाएँ और संवाद शैली में अंतर आना स्वाभाविक है। माता-पिता जहां अपेक्षा करते हैं कि बच्चे उनकी बात बिना प्रश्न किए मान लें, वहीं बच्चे चाहते हैं कि उनकी राय को भी महत्व दिया जाए। यही कारण है कि कई बार संवाद टकराव का रूप ले लेता है।

यह भी सच है कि बदलती शैली ने रिश्तों में पारदर्शिता और खुलापन बढ़ाया है। अब बच्चे माता-पिता से अपने करियर, दोस्ती, प्रेम और जीवन की उलझनों के बारे में खुलकर बात करने लगे हैं। पहले जिन विषयों पर चुप्पी साधी जाती थी, अब उन पर सहज बातचीत संभव है। संवाद का यह नया रूप परिवारों को अधिक लोकतांत्रिक और सहयोगी बना रहा है। बदलती संवाद शैली

यह भी सच है कि बदलती शैली ने रिश्तों में पारदर्शिता और खुलापन बढ़ाया है। अब बच्चे माता-पिता से अपने करियर, दोस्ती, प्रेम और जीवन की उलझनों के बारे में खुलकर बात करने लगे हैं। पहले जिन विषयों पर चुप्पी साधी जाती थी, अब उन पर सहज बातचीत संभव है। संवाद का यह नया रूप परिवारों को अधिक लोकतांत्रिक और सहयोगी बना रहा है। बदलती संवाद शैली के साथ चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं।

के साथ चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। व्यस्त जीवन, तनाव और तकनीकी लत के कारण प्रत्यक्ष संवाद का समय घटता जा रहा है। परिवार एक साथ होते हुए भी मोबाइल स्क्रीन में खोए रहते हैं। संवाद का मानवीय पक्ष, जिसमें आँखों का भाव, आवाज की गर्मजोशी और स्पर्श की आत्मीयता शामिल है, धीरे-धीरे कम हो रहा है। यही कमी रिश्तों में दूरी और गलतफहमियां पैदा करती है। माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद स्वस्थ रहे, इसके लिए दोनों पक्षों को प्रयास करने होंगे। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों की भावनाओं और विचारों को सुनने का धैर्य रखें। बच्चों को यह महसूस कराना जरूरी है कि उनकी राय महत्वपूर्ण है। वहीं बच्चों को भी यह समझना चाहिए कि माता-पिता का अनुभव अमूल्य है और उनके सुझाव केवल अनुशासन के लिए नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा और भलाई के लिए होते हैं।

परिवारों में 'फेस-टू-फेस संवाद' की परंपरा को पुनर्जीवित करने की पुनः आवश्यकता है। भोजन के समय, सैर पर जाते हुए या छुट्टियों में तकनीक से दूरी बनाकर सीधे संवाद किया जाए। इसी से रिश्तों में गर्माहट बनी रह सकती है। संवाद की शैली चाहे बदले, पर इसका उद्देश्य सदैव एक ही रहता है। पारस्परिक समझ, सहयोग और प्रेम। यदि माता-पिता और बच्चे बदलते समय के साथ संवाद के इस नए स्वरूप को संतुलन और आत्मीयता के साथ अपनाएँ, तो पीढ़ियों के बीच दूरी घट सकती है। संवाद ही वह धागा है, जो परिवार के मोतियों को एक सूत्र में बांधता है। इसलिए आवश्यक है कि यह धागा कभी कमजोर न हो, बल्कि समय के साथ और मजबूत होता जाए।

मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा

रवि रंजन कुमार

शारदीय नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो देवी दुर्गा की पूजा और उत्सव के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान लोग देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं और उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि साल में दो बार आता है। इनमें एक चैत्र मास के नवरात्र व दूसरी शारदीय नवरात्र। इनमें शारदीय नवरात्र का खास महत्व है। शारदीय नवरात्र मुख्य रूप से मां दुर्गा की पूजा और आराधना के लिए मनाया जाता है। मां दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है और उनकी पूजा से भक्तों को ज्ञान, साहस और शक्ति प्राप्त होती है।

इस दौरान लोग अपने घरों, दुकानों और

दफ्तरों को सजाते हैं। जगह-जगह मां दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं. पूजा-पाठ, भजन और कीर्तन का आयोजन होता है।

नवरात्रि के नौ दिन देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है, जिन्हें 'नवदुर्गा' कहा जाता है। यह त्योहार अश्विन मास में मनाया जाता है। नवमी के बाद दशहरे पर समाप्त होता है। दशहरे के दिन रावण दहन भी किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्र के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के ये नौ रूप नीचे दिये गये हैं।

शैलपुत्री: नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। यह मां दुर्गा का पहला रूप है और इन्हें वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है।

ब्रह्मचारिणी: दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो तपस्या और साधना की प्रतीक हैं. इन्हें माता पार्वती के अविवाहित रूप में पूजा जाता है। इनके एक हाथ में रुद्राक्ष माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है।

चंद्रघंटा: तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ये अपने भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती हैं। इनका रूप चमकते चंद्रमा की तरह सुंदर और शक्तिशाली है।

कूष्मांडा: चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है उनका नाम कूष्मांड नामक दैत्य को मारने से जुड़ा है। यह देवी दुर्गा का शक्तिशाली रूप है।

स्कंदमाता: पांचवे दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। यह भगवान कार्तिकेय की माता हैं, और इनकी पूजा से दुश्मनों का नाश होता है।

कात्यायनी: छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है. इनका जन्म महिषासुर का अंत करने के लिए हुआ था। ये देवी शक्ति का एक और रूप हैं।

कालरात्रि: सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह मां दुर्गा का भयानक रूप है, जो सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं।

महागौरी: आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। ये सुंदर और गोरी देवी हैं, और इनकी पूजा से सुख-समृद्धि प्राप्त होती है।

सिद्धिदात्री: नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनकी चार भुजाएं होती हैं और ये सिंह पर सवार होती हैं।

शारदीय नवरात्र 2025 घटस्थापना मुहूर्त

22 सितंबर को घटस्थापना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 09 मिनट से लेकर सुबह 08 बजकर 06 मिनट तक है। इस दौरान किसी भी समय घटस्थापना कर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 49 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक है।

घटस्थापना की सामग्री लिस्ट

- मिट्टी का बर्तन
- कलश
- अखंड ज्योति के लिए बड़ा दीया, रुई की बाती
- जटा वाला नारियल
- आम या अशोक के पत्ते
- गंगाजल
- लाल कपड़ा
- किसी पवित्र स्थान की मिट्टी (मंदिर आदि)
- अक्षत, हल्दी
- फूल, फूल माला
- इलायची, लौंग, कपूर
- लाल सूत्र, सिक्का
- सुपारी, मौली, रोल
- ऐसे करें मां दुर्गा को प्रसन्न

अगर आप शारदीय नवरात्र में माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो रोजाना पूजा-अर्चना कर मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करेंधार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से माता रानी प्रसन्न होकर साधक को धन-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है।

पार्टी में पाएं रॉयल और क्लासी लुक

अगर आप भी ब्रोकेड पैंट्स स्टाइल करने का मन बना रही हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। क्योंकि आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसे ही स्टाइलिंग टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ब्रोकेड पैंट्स स्टाइल करने के समय बहुत काम आएंगे।

आकांशा गर्ग

ब्रोकेड पैंट्स का अपना एक खास लुक होता है। जब आप पार्टी के लिए कुछ वेस्टर्न या फिर इंडो वेस्टर्न कैरी करना चाहती हैं, तो ऐसे में ब्रोकेट पैंट्स को स्टाइल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ब्रोकेट पैंट का लुक, टेक्सचर और डिजाइन और एलिगेंट और क्लासी लुक देने में मदद करता है। इसलिए हर महिला और लड़की को इसको अपने वार्डरोब में जरूर शामिल करना चाहिए। हालांकि महिलाएं एक स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए एक्सेसरीज का भी सहारा लेती हैं। लेकिन ब्रोकेट पैंट्स खुद में ऐसा स्टाइल स्टेटमेंट है, तो आपको एक्सेसरीज या फिर अन्य चीजों को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है।

इन पैंट्स की एक खासियत यह भी होती है कि आप इसको वेस्टर्न वियर के साथ भी पेयर कर सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यह इंडियन वियर के साथ भी काफी ज्यादा स्टनिंग लगते हैं। इसके लिए बस आपको सही तरह से इसे स्टाइल करने की जरूरत होती है। हालांकि ब्रोकेड पैंट्स को स्टाइल करने के दौरान हम अपने लुक को ओवर कर देते हैं, जिस वजह से पूरा लुक खराब हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी ब्रोकेड पैंट्स स्टाइल करने का मन बना रही हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। क्योंकि आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसे ही स्टाइलिंग टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ब्रोकेड पैंट्स स्टाइल करने के समय बहुत काम आएंगे।

टेक्सचर के साथ करें एक्सपेरिमेंट

ब्रोकेड पैंट्स में एक रॉयल के साथ एलिगेंट और क्लासी लुक पाने के लिए अपने टेक्सचर के साथ थोड़ा प्ले करें। ब्रोकेड पैंट्स काफी रिच लुक देने का काम करती है। क्योंकि ये टेक्सचर्ड व थोड़ी शाइनी होती हैं। इसलिए अगर आपका अपर वियर का फैब्रिक ज्यादा हैवी या शाइनी है, तो इसमें आपका लुक थोड़ा अजीब लग सकता है। कोशिश करें कि आप अपर वियर के लिए साटन, सिल्क या शिफॉन जैसे फैब्रिक चुनें। अगर आप रॉयल लुक पाना चाहती हैं, तो आप ब्रोकेड में मोनोक्रोम लुक भी कैरी कर सकती हैं।

कलर्स का ध्यान रखें

आप भी भी ब्रोकेड पैंट्स को पहनती हैं तो आपको ओवर ऑल लुक में कलर को बैलेंस्ड तरीके से कैरी करना चाहिए। इसके लिए आपके वियर का कलर ऐसा होना चाहिए, जो आपकी पैंट्स में भी शामिल हो। अगर आपकी ब्रोकेड पैंट्स में रेड, गोल्ड या डीप ज्वैल टोन है, तो आप को-ऑर्डिनेट लुक के लिए भी ऐसी ही कलर को अपर वियर के लिए चुनें। वहीं न्यूट्रल शेड्स में क्रीम, ब्लैक, बेज या ऑफ व्हाइट भी आपके लुक को खास बनाने का काम करेगा।

फिटिंग में ना हो गड़बड़

- हम अक्सर ब्रोकेड पैंट्स में फ्लेयर्ड, स्ट्रेट या वाइड लेग को चुनते हैं।
- वहीं शार्प और क्लासी लुक पाने के लिए आपको हमेशा फिटेड टॉप को अपने लुक का हिस्सा बनाना चाहिए।
- इससे आपको फिनिश्ड लुक मिलेगा और अगर आप हाई-वेस्ट ब्रोकेड पैंट पहन रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में टॉप को अंदर की तरफ टक करना न भूलें।

हेयरस्टाइल के लिए महंगी एक्सेसरीज क्यों, घर की ज्वेलरी से पाएं नया ग्लैमरस लुक

क्या आप जानती हैं कि आप हेयरस्टाइल में झुमके या मांग टीका जैसी ज्वैलरी को कैरी कर सकती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसी ही ज्वैलरी के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनको आप अपनी हेयरस्टाइल का हिस्सा बना सकती हैं।

जब भी खुद को स्टाइल करने की बात आती है, तो हम सभी अपने एक्सेसरीज और आउटफिट पर अधिक फोकस रहते हैं। लेकिन एक्सेसरीज और आउटफिट के साथ हेयरस्टाइल भी बहुत मायने रखता है। लड़कियां तरह-तरह के हेयरस्टाइल करना पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप हेयर स्टाइल को एक नया ट्विस्ट देना चाहती हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आप अपनी ज्वेलरी को अपने लुक का हिस्सा बना सकती हैं। ऐसा करने से आपका पूरा लुक ग्लैमरस नजर आएगा। अभी तक हम सभी हेयर पिन से लेकर क्लचर या रबर बैंड का इस्तेमाल हेयरस्टाइल में करते आए हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि आप हेयरस्टाइल में झुमके या मांग टीका जैसी ज्वैलरी को कैरी कर सकती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसी ही ज्वैलरी के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनको आप अपनी हेयरस्टाइल का हिस्सा बना सकती हैं।

बन पिन की तरह कैरी करें झुमका

अगर कान का एक झुमका खो गया है, तो आपके परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप इसकी मदद से अपने हेयर स्टाइल को एक न्यू लुक दे सकती हैं। आप झुमके को बन पिन की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप किसी पार्टी या फिर फंक्शन में जा रही हैं, तो आप बन बनाकर झुमके का हुक अंदर की तरफ फंसा लें।

इस तरह से आपके हेयर स्टाइल को नया ट्विस्ट मिल जाएगा।

हेयर चेन की तरह कैरी करें चेन इयररिंग्स

अगर आपके पास चेन इयररिंग्स हैं, तो आप इसको अपने हेयर स्टाइल का हिस्सा बना सकती हैं। ओपन वेव्स लुक या फिर साइड ब्रेड हेयरस्टाइल के साथ चेन इयररिंग्स काफी अच्छी लगेगी। जब आप साइड से चेन वाले इयररिंग्स को पिन करती हैं तो इससे हेयर चेन जैसा लुक आएगा।

ऐसे पहनें मांग टीका

हम सभी बालों के बीच मांग निकालकर मांगटीका को पहनते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर इसी तरह पहनें। आप इसको साइड पार्टिंग में क्लिप की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप एथनिक आउटफिट कैरी कर रही हैं और उसके साथ मैसी बन हेयर स्टाइल बनाएं, फिर उसके ऊपर मांगटीका लगाएं।

हेयर बैंड की तरह लगाएं चोकर

अब हम सभी इंडियन से लेकर इंडो-वेस्टर्न आउटफिट के साथ चोकर को स्टाइल करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि चोकर एक बेस्ट हेयर एक्सेसरीज भी साबित हो सकती है। आप चोकर नेकपीस को बतौर हेयरबैंड की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए आपकी स्लीक पोनीटेल या फिर ओपन कर्ल्स हेयर लुक रखें। फिर उसके साथ चोकर को हेयरबैंड की तरह पहनें। अगर आपने इंडो वेस्टर्न आउटफिट पहना है, तो उसके साथ यह आपको काफी अच्छा लुक देगा।

श्रद्धा और शक्ति का अद्वितीय धाम है पावागढ़ कालीका माता मंदिर

पावागढ़ का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर को शक्ति साधना और तांत्रिक परंपरा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार, यहाँ पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

अरुण मिश्रा

गुजरात के पंचमहल ज़िले में स्थित पावागढ़ कालीका माता मंदिर भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 800 मीटर ऊँची पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं, पर्यटकों और साहसिक यात्रियों सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ देवी कालीका माता की पूजा होती है और मान्यता है कि यहाँ सती का दायां पैर गिरा था, जिसके कारण यह स्थान शक्ति पीठ कहलाता है।

ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व

पावागढ़ का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर को शक्ति साधना और तांत्रिक परंपरा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार, यहाँ पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। यह स्थल चंपानेर-पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है।

मंदिर की विशेषताएँ

मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं या फिर रोपवे का सहारा लिया जा सकता है। गर्भगृह में देवी कालीका माता की प्रतिमा प्रतिष्ठित है, जिन्हें लाल रंग के वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। मंदिर से आसपास की हरियाली, पहाड़ और दूर-दूर तक फैले प्राकृतिक नजारे दिखाई देते हैं।

उत्सव और धार्मिक आयोजन

नवरात्रि पर्व पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। भक्ति संगीत, गरबा और देवी की आराधना से पूरा परिसर गूंज उठता है। पूरे वर्ष विभिन्न अवसरों पर यहाँ मेले और धार्मिक आयोजन होते रहते हैं।

साहसिक और पर्यटन आकर्षण

मंदिर तक पहुँचने का रास्ता रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। रोपवे की सवारी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास अनुभव देती है।

चंपानेर का किला, जामा मस्जिद और अन्य पुरातात्विक धरोहरें भी पास ही स्थित हैं, जिन्हें देखकर पर्यटक इतिहास और संस्कृति का आनंद ले सकते हैं।

कैसे पहुँचे?

- **निकटतम हवाई अड्डा:** वडोदरा (लगभग 50 किमी)
- **रेलवे स्टेशन:** हलोल और वडोदरा
- **सड़क मार्ग:** अहमदाबाद, वडोदरा और गोधरा से सड़क द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है।

पावागढ़ कालीका माता मंदिर श्रद्धा, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। यह मंदिर न केवल शक्ति साधना का पावन धाम है, बल्कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ आकर श्रद्धालु देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पर्यटक संस्कृति तथा प्रकृति दोनों का अद्भुत अनुभव करते हैं।

जोखिम व रोमांच से भरपूर किला

आज तकनीक के जरिये दुनिया भर में आंख चौंधिया देने वाली इमारतें दिखाई देती हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसे प्राचीन किले हैं, जिनका निर्माण आश्चर्य पैदा करता है। हरिहर फोर्ट ऐसे ही किलों में शुमार है।

कोई इसे हर्षगढ़ किला कहता है तो कोई हरिहर फोर्ट। महाराष्ट्र में स्थित सह्याद्री पर्वतमाला में बने इस पहाड़ी किले को देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। इसे कैसे बनाया गया होगा? आखिर क्यों बनाया गया होगा? जिस किले को देखने के लिये जान जोखिम में डालनी पड़ती है, उसे बनाने में कितना जोखिम लिया गया होगा? ऐसे तमाम सवाल इस किले को देखकर मन में उठने लगते हैं। ऐसे ही सवाल इस किले को देखने-समझने की उत्सुकता पैदा करते हैं।

नासिक जिले के कसारा नामक जगह पर स्थित है हरिहर फोर्ट। इसकी खड़ी चढ़ाई इतनी खतरनाक है कि हर कोई इस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि पूरे साल इसे देखने जाने वालों की लाइन लगी रहती है। युवाओं के लिये तो यह फोर्ट आकर्षण का केन्द्र रहता है और वे इसे देखने का रोमांच खोना नहीं चाहते। यह फोर्ट एक त्रिकोणीय आकार की बहुत ऊंची और विशाल चट्टान पर बना हुआ है, जो इसे अन्य किलों से अलग और अद्वितीय बनाता है। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि हरिहर किले का निर्माण यादव राजवंश ने कराया था, जिसका महाराष्ट्र में 9वीं से 14वीं शताब्दी के शासन था। कहा गया है कि इस किले का निर्माण व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए कराया गया था। खासकर गोंडा घाट से गुजरने वाले मार्गों की सुरक्षा के लिये। साल 1636 में हरिहर किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी त्र्यंबक और पुणे के अन्य किलों के साथ खान जमम को सौंप दी गई थी। वर्ष 1818 में 17 अन्य किलों के साथ इस किले पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ब्रिटिश हुकूमत के कैप्टन ब्रिग्स के नेतृत्व में यह किला अंग्रेजों के अधीन हो गया था। हरिहर किले में कोई अच्छी संरचना नहीं बची है, सिवाय एक छोटे से प्रवेश द्वार वाले भंडारण गृह के। किले के केंद्र में चट्टानों को काटकर बनाए गए पानी के कुंडों की एक श्रृंखला है, जो यादव राजवंश और अंग्रेज हुकूमत के दौरान सैनिकों के पीने-नहाने के काम आती होगी। इतिहास में दर्ज है कि ब्रिटिश हुक्मरानों ने इस किले के दरवाजे को नष्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन इसकी संरचना और इसके पत्थरों में खुदी सीढ़ियों को देखकर वे अपने फैसले से पीछे हट गए। इस ऐतिहासिक किले तक पहुंचने के लिये खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस तक जाने के लिये पत्थरों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई थीं। अक्सर बारिश होने की वजह से ये सीढ़ियां इतनी चिकनी होती हैं कि कभी भी फिसलने से मौत के आगोश में पहुंच सकते हैं। कई लोग इस किले को हर्षगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे हर्षवाड़ी नामक एक गांव स्थित है। किले तक पहुंचने के लिये इस गांव से होकर ही जाना होता है। हरिहर किले पर सबसे ज्यादा शासन मराठाओं का रहा है। मराठा सैनिक इस किले से ही दुश्मन पर नजर रखते थे और इसे महाराष्ट्र में व्यापार के लिये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। किले की सीढ़ियां उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत कारीगरी थीं। इतिहास पर नजर डालें तो यादव राजवंश के बाद हरिहर किला कई साल तक निजाम शाह के अधीन रहा। साल 1636 में शाहजी राजे ने इसे जीत लिया। बाद में यह किला मुगलों के पास चला गया। वर्ष 1670 में मराठा वीर मोरोपंत पिंगले ने इसे एक स्वतंत्र किला बना लिया और फिर 1818 में अंग्रेजों ने इसे मराठों से छीन लिया।

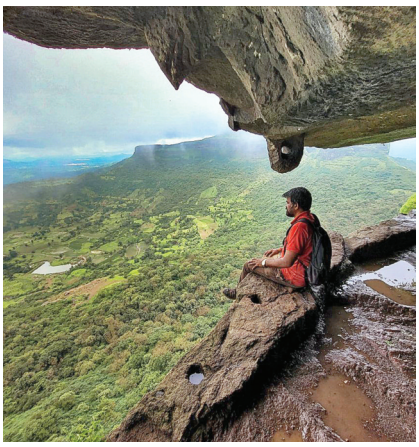

टिप्स: बस रोजाना एक चम्मच घी खाने से मिलेंगे अद्भुत फायदे

डॉ. मुकुल शर्मा

30 की उम्र में महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव आते हैं। इस अवधि में सबसे ज्यादा हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अगर महिलाएं रोजाना 1 चम्मच घी खाएं तो इससे इन्हें कई सारे फायदे मिलेंगे। घी में कई सारे गुण पाएं जाते हैं।

अक्सर 30 की उम्र के बाद महिलाओं के बॉडी में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। वैसे भी उम्र के अलग-अलग पड़ाव में खान-पान का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। एज के हिसाब से बॉडी की न्यूट्रिशनल जरुरत को पूरा करने के लिए एक हेल्दी रूटीन को जरुर फॉलो करें, जिससे शरीर भी मजबूत बना रहेगा। 30 की उम्र के बाद महिलाओं में कई हार्मोनल बदलाव आते हैं। इस दौरान मेटाबॉलिज्म भी धीमा होने लगता हैं और हड्डियों के लिए अत्यधिक पोषण चाहिए होता है। इसलिए महिलाओं को 30 के उम्र के बाद घी का सेवन जरुर करना चाहिए।

30 की उम्र के बाद महिलाएं एक चम्मच घी जरुर खाएं

- इस उम्र के दौरान महिलाओं में हार्मोनल इंबैलेंस शुरू हो जाते हैं। 30 की उम्र में महिलाओं का मूड, एनर्जी लेवल और पीरियड साइकिल पर होता है। ऐसे में एक चम्मच घी खाने से शरीर मजबूत बनता है। इसके साथ ही हार्मोंस का बैलेंस करने में मदद मिलती है।
- घी में हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जो हार्मोनल हेल्थ को दुरुस्त करता है और शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस करते हैं।
- 30 के बाद महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है और हड्डियों के कमजोर होने से दिक्कत बढ़ जाती है। घी मे पाया जाता है विटामिन- डी और विटामिन- के जो शरीर में कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं।

- घी के सेवन करने से जोड़ों में मजबूती बनीं रहती है और अर्थराइटिस की दिक्कत नहीं होती है।
- घी में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और ब्यूरेटिक एसिड, मेंटल हेल्थ के लिए भी जाना जाता है।
- 30 के बाद बाद मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगाता है। इसलिए घी का सेवन करने से पाचन तंत्र स्ट्रांग बना रहता है और कब्ज की समस्या से दूर होती है और आंतों की सूजन कम हो जाती है।
- घी को सही मात्रा में खाने से कभी वजन नहीं बढ़ता है। इसलिए महिलाएं एक चम्मच घी रोजाना जरुर लें।
- घी का सेवन करने से एजिंग साइन्स दूर होने लगते हैं और बाल भी झड़ने कम हो जाते हैं। घी खाने से त्वचा को हाइड्रेशन और ग्लो प्रदान होता है।

बदलते मौसम में खराश ने जकड़ लिया गला करें इन 3 काढ़ों का सेवन, दूर होगी समस्या

डॉ. निमित त्यागी

बदलते मौसम में गले की खराश एक आम समस्या है, जिससे निजात पाने के लिए यह लेख तीन प्रभावी आयुर्वेदिक काढ़ों का सुझाव देता है। हल्दी, तुलसी और अदरक जैसे प्राकृतिक तत्वों से बने ये काढ़े न केवल गले के दर्द और संक्रमण से राहत दिलाते हैं बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करते हैं।

धीरे-धीरे मौसम में काफी बदलाव आ रहा है। बदलते मौसम में कई सारी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस मौसम में अधिकत्तर गले में खराश बनीं रहती है। गले में खराश होने से बार-बार असहज महसूस होता है, कई बार तो खराश की वजह से व्यक्ति अपनी बात को सही प्रकार से दूसरे के सामने रख नहीं पाती हैं। लंबे समय खराश की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप इन काढ़ों का सेवन कर सकते हैं, इससे आपके गले की खराश दूर हो जाएगी। आइए आपको बताते हैं गले की खराश को दूर के लिए काढ़े।

हल्दी, शहद और काली मिर्च का काढ़ा

इस काढ़े को बनाने के लिए एक गिलास पानी में हल्दी को मिक्स करें और चुटकी भर काली मिर्च मिलाएं। इस मिश्रण को उबाल लीजिए और इसे छानकर सेवन करें। आप चाहें तो इस मिश्रण में शहद भी मिला सकते हैं। हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो दर्द व सूजन में राहत दिलाते हैं। काली मिर्च कप में राहत देते हैं।

दालचीनी, लौंग और तुलसी का काढ़ा

गले की खराश में इन तीनों का मिश्रण राहत पहुंचाएगा। दालचीनी में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जबकि लौंग के सेवन से इन्फेक्शन को दूर किया जाता है। इसे बनाने के लिए आप एक गिलास पानी में दालचीनी का पाउडर और लौंग को तुलसी के पत्तों के साथ उबालें और इसे छानकर पिएं। ऐसा करने से आपके गले की खराश खत्म हो जाएगी।

अदरक- तुलसी का काढ़ा

बदले मौसम में गले की खराश, सर्दी-जुकाम के लिए यह काढ़ा बेहद फायदेमंद है। अदरक में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी मौजूद होते हैं। तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करती है। इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में अदरक का टुकड़ा कूटकर डालें और साथ ही में चार-पांच तुलसी के पत्ते डाल दें। इस मिश्राण को उबाल लें। इस काढ़े को छान कर सेवन करें। इसमें शहद भी मिला सकते हैं, शहद ऑप्शनल है।

मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा

तो इस तरह बॉबी देओल ने तय किया फ्लॉप से लॉर्ड बनने का सफर

बॉबी देओल का बॉलीवुड करियर एक रोलरकोस्टर राइड की तरह है। इस सफल में आपको सबकुछ देखने मिलने वाला है। बॉबी देओल का एक समय पर बॉलीवुड में जलवा रहा, तो वहीं 10 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद वो गायब हो गए। लेकिन जब वापसी की तब सबकी बोलती बंद कर दी।

कल्पना कीजिए, एक ऐसा हीरो जो सिल्वर स्क्रीन पर घोड़े दौड़ाता हो, दुश्मनों को धूल चटाता हो और दिलों में 'हलचल' पैदा कर दे ला दे। लेकिन अचानक वही हीरो कहीं गुम हो जाए। न कोई फिल्म, न कोई तालियां, बस एक खालीपन। और फिर एक दिन वो लौटे तो, न सिर्फ हीरो, बल्कि विलेन बनकर सबको चौंका दें। ये बॉबी देओल की कहानी है, जहां फ्लॉप की काली रातों ने उन्हें तोड़ा, लेकिन वापसी की सुबह ने नया जन्म दिया। जी हां, बॉबी देओल का सफर बॉलीवुड का वो रोलरकोस्टर है, जो आपको हंसाएगा, रुलाएगा, और अंत में तालियां बजवाएगा। तो चलिए इस 'लॉर्ड' की जिंदगी की किताब पलटते हैं, जहां हर पन्ना एक ट्विस्ट से भरा है।

बॉबी देओल की पर्सनल लाइफ

बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1969 को मुंबई में हुआ था। बॉबी देओल ने बचपन में ही 'धर्मवीर' (1977) में चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में धमाल मचाया। लेकिन असली धमाका तो 1995 में फिल्म 'बरसात' से हुआ। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और इसके लिए बॉबी को फिल्मफेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवॉर्ड मिला। वो दौर था जब लंबे बाल, मास्कुलिन लुक और एक्शन का कम्बिनेशन बॉलीवुड का फॉमूर्ला था। 1990 के दशक के अंत तक, बॉबी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ नेपो किड नहीं, बल्कि टैलेंटेड स्टार भी हैं। 1997 की 'गुप्त' एक थ्रिलर

जो आज भी काफी पसंद की जाती है। फिर आई फिल्म 'सोल्जर' जिसने बॉबी देओल को एक अलग ही पहचान दिलाई। साल 2000 में 'बादल' और 'बिच्छू' दोनों ही फिल्में हिट साबित हुईं। 2001 की 'अजनबी' में बॉबी विलेन बने, लेकिन हीरो जैसे चमके। 2002 की 'हमराज' ने उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन दिलाया। वो दौर था जब बॉबी की फैन फॉलोइंग सलमान-अक्षय को टक्कर दे रही थी।

करियर में आई गिरावट

फिर आया वो मोड़, जहां स्टारडम की चमक फीकी पड़ने लगी। 2000 के दशक के मिडल में, बॉलीवुड बदल रहा था। ऋतिक रोशन, शाहरुख खान का डोमिनेशन देखने को मिल रहा था। बॉबी के साथ समस्या ये थी कि वो पुराने फॉमूर्ले में अटक गए थे। गलत स्क्रिप्ट चॉइस की वजह से करियर नीचे की तरफ जाता रहा। बॉबी देओल की एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। 2007 की 'झूम बराबर झूम' ने करियर को और गर्त में डाल दिया। बॉबी देओल ने बाद में खुद कबूला, 'मैंने गलत रोल चुने, इंडस्ट्री के बदलाव को नहीं समझा। कई रोल जो मेरे लिए थे, वो दूसरों को चले गए।' 2010 तक कंसिस्टेंट 11 फिल्में फ्लॉप रही, जिसे बाद बॉबी देओल घर में सन्नाटा छा गया।

पूरी तरह टूट गए बॉबी देओल

इसी डार्क फेज में आया 'ऊख बॉबी' का चैप्टर, जो आज मीम्स का राजा है, लेकिन तब 'मिलिएशन था। 2014-2016 तक बॉबी देओल को फिल्में मिलनी बंद हो गई थीं। जिसके बाद बॉबी देओल ने कुछ ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। बॉबी देओल इस दौरान दिल्ली के एक इवेंट में गए और वहां मैनेजमेंट ने उन्हें ऊख की पोजिशन ऑफर की और बिना मन के बॉबी देओल ने ये काम शुरू किया। लेकिन यहां भी बॉबी देओल से एक भारी गलती हो गई। उन्होंने इवेंट में अपनी फिल्म 'गुप्त' के गाने लूप पर चला दिए। जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ भड़क गई और रिफंड मांगने लगी। ये फेज उनके लिए शर्मिंदगी से भरा था, लेकिन आज 'ऊख बॉबी' उनके ब्रांड का हिस्सा।

एक धमाकेदार वापसी

'मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा' ये लाइन बॉबी देओल की लाइफ पर एकदम फिट बैठती है। 2017 में बॉबी देओल का करियर उस मोड़ पर था, जहां सन्नाटा पसरा था। लेकिन कहते हैं न, 'जब रात सबसे गहरी हो, सुबह करीब होती है।' भाई सनी देओल के साथ 'पोस्टर बॉयज' में बॉबी ने छोटा सा रोल निभाया। फिल्म कोई बड़ा धमाका नहीं थी, लेकिन ये वो पहला कदम था, जिसने बॉबी को फिर से सेट पर ला खड़ा किया। 2018 में मिले सलमान खान के साथ ने सब कुछ बदल दिया। फिल्म 'रेस 3' बॉबी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद 'हाउसफुल 4' और ओटीटी पर भी बॉबी देओल ने धमाल किया। लेकिन असली धमाका तो 2023 में हुआ, जब संदीप रेड्डी वंगा ने 'एनिमल' में बॉबी को एक ऐसा रोल दिया जिसने बॉलीवुड की नींव हिला दी। अब वो वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने रोल से लोगों का दिल जीत रहे हैं। अब लॉर्ड बॉबी उस मुकाम पर है, जहां पहुंचने का हर कोई सपना देखता है।

ये खिलाड़ी भी लेंगे सन्यास !

भारतीय क्रिकेट टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। दुनिया में टीम इंडिया का परचम बुलंदियों तक ले जाने वाले कुछ स्टार खिलाड़ी टेस्ट या फिर टी-20 से सन्यास ले चुके हैं तो कुछ सन्यास के लिये लाइन में हैं। इनके बिना नई टीम के लिये बड़ी चुनौतियां पेश होंगी।

नई टीम इंडिया चयनकर्ता अजित अगरकर और कोच गौरम गंभीनर के लिये बड़ी चुनौती साबित हो रही है। टेस्ट और टी-20 फॉर्मेट से रोहित शर्मा और विराट कोहली के सन्यास के बाद चूंकि कुछ और सितारे सन्यास लेने जा रहे हैं, लिहाजा उनके विकल्प खोजना आसान नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि टेस्ट टीम हो या वनडे या फिर टी20, तीनों फॉर्मेट में बदलाव का दौर चल रहा है और दिग्गज खिलाड़ियों का सही विकल्प ढूंढना

महमूद रजा
बिजनौर

आसान हरगिज नहीं होगा। खासकर इसलिये कि बड़बोले कोच गौतम गंभीर की अकड़-मकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है।

टी20 क्रिकेट से स्टार खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने पहले ही सन्यास ले लिया था। इसके बाद रोहित व कोहली समेत सुपर-डुपर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट से भी सन्यास ले लिया। चर्चा है कि इस कड़ी में कुछ और दिग्गज भी सन्यास की घोषणा करने की तैयारी में हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जो विराट कोहली की तरह इनफार्म हैं तो कुछ लंबे समय तक टीम इंडिया का हिस्सा रहने के बावजूद अब खेलते हुए नजर नहीं आते। उनसे इशारे में कहा जा चुका है कि अब उनकी

भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी मुश्किल है। आखिर कौन-कौन खिलाड़ी हैं, जो भविष्य में किसी भी फार्मेट में टीम इंडिया के सदस्य नहीं होंगे और सन्यास ही उनके लिये एकमात्र विकल्प बचा है।

उमेश यादव

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ साल में वे सभी फॉर्मेट से बाहर हैं। उन्होंने भारत के लिए 2023 में अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था। इसके बाद उनकी टीम में कोई जगह नहीं है। चर्चा है कि उमेश यादव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास का ऐलान किसी भी समय कर सकते हैं। उन्होंने भारत के लिए 57 टेस्ट में 170, 75 वनडे में 105 और 9 टी20 में 12 विकेट लिए हैं। जाहिर है कि उमेश यादव ने भारतीय क्रिकेट को शानदार योगदान दिया है, लेकिन अब चूंकि उनकी वापसी के आसार नहीं हैं, लिहाजा उनके सामने सन्यास की घोषणा करना ही एकमात्र विकल्प बचा है।

इशांत शर्मा

टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में हैं जो लंबे समय से टीम से बाहर हैं। पूर्व खिलाड़ियों की राय है कि इशांत की वापसी भी अब मुमकिन नहीं है। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट 2021 में खेला था। इसके बाद उन्हें आईपीएल के मैचों में गेंदबाजी करते ही देखा गया। उन्होंने भारत के लिए 105 टेस्ट में 311 विकेट, 80 वनडे में 115 और 14 टी20 में 8 विकेट अपने नाम किए हैं। क्रिकेट में शानदार उपस्थिति दर्ज करा चुके इशांत के सामने अब सन्यास की घोषणा के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। चर्चा है कि वे जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास का ऐलान करने वाले हैं।

रविंद्र जडेजा

शानदार भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों की कतार में हैं। फिलहाल भारतीय टीम में सबसे उम्रदराज यह ऑलराउंडर अभी भी इनफार्म है और टीम इंडिया के लिये कर्णधार की भूमिका निभाते दिख रहा है, लेकिन चर्चा है कि इंग्लैंड सीरीज के बाद जडेजा टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले लेंगे और वर्ल्डकप में अगर उन्हें शामिल किया गया तो यह उनका आखिरी टूनार्मेंट होगा। फिलहाल भारतीय टीम में जडेजा से बेहतर कोई ऑलराउंडर नहीं है और उनका विकल्प तलाशना मुश्किल काम होगा।

चेतेश्वर पुजारा

भारतीय क्रिकेट टीम के मजबूत बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को भी टेस्ट टीम से बहुत पहले ही बाहर किया जा चुका है। पुजारा ने अपना अंतिम टेस्ट मैच 2023 में खेला था। रोहित और विराट जैसे दिग्गजों के बाद उनकी भी टीम इंडिया में वापसी की कोई उम्मीद नहीं रह गई है। भारत-इंग्लैंड सीरीज में एक्सपर्ट कमेंटेटर की भूमिका निभाने वाले पुजारा ने 103 टेस्ट मैचों में 7195 रन बनाए हैं। उनके नाम 5 वनडे में 51 रन भी दर्ज हैं। टेस्ट क्रिकेट के इस भरोसेमंद बल्लेबाज के सामने भी क्रिकेट से सन्यास का ऐलान करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है।

अजिंक्य रहाणे

भारत के दाएं हाथ के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अपना अंतिम टेस्ट मैच 2023 में खेला था। इसके बाद उन्हें पिछले दिनों आईपीएल टूनार्मेंट में बल्लेबाजी का धमाल मचाते देखा गया। अगरकर-गंभीर की जोड़ी ने इस खिलाड़ी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। रहाणे ने क्रिकेट के हर फार्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 85 टेस्ट में 5077 रन बनाए है। उनके नाम 90 वनडे में 2962 और 20 टी20 में 375 रन दर्ज हैं। अब रहाणे भी संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों की कतार में खड़े नजर आ रहे हैं।

WI
welcome
INDIA
PACKAGED DRINKING WATER
WI
welcome
INDIA
PACKAGED DRINKING WATER
WI
welcome
INDIA
PACKAGED DRINKING WATER

SHANTI NATH MANUFACTURERS
A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com
Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

महिलाओं के पक्ष में रजिस्ट्री कराएं स्टाम्प शुल्क में आकर्षक छूट पाएं

"महिलाओं को ₹10 लाख तक की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट दी जा रही थी। इसे बढ़ाकर अब ₹1 करोड़ तक की रजिस्ट्री पर लागू कर दिया गया है। आइए, माताओं, बहनों एवं बेटियों के पक्ष में रजिस्ट्री करवाकर उनके आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दें।"

-योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

स्टाम्प शुल्क में छूट

महिलाओं/बेटियों के पक्ष में निष्पादित होने वाले विलेखों (डीड्स) पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में बड़ी राहत

छूट की सीमा

महिलाओं/बेटियों के पक्ष में निष्पादित विलेखों (डीड्स) पर स्टाम्प शुल्क में ₹1 करोड़ तक के मूल्य पर 1%

योजना का उद्देश्य

महिलाओं/बेटियों के संपत्ति पंजीकरण में वृद्धि करना है, जिससे वह आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें

छूट की सीमा में 10 गुना तक विस्तार

- ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ तक के विलेखों पर लाभ
- विलेख का मूल्यांकन ₹1 करोड़ से अधिक होने पर भी ₹1 लाख तक की छूट

काम दमदार-डबल इंजन सरकार

UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश